● वर्ष : 17 ● अंक : 246 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

WWW.LKSTV.IN

# दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शुक्रवार 26 जून 2026

# वेनेज़ुएला में आए दो भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 164 और 971 घायल

## एक मिनट में लगे दो बड़े झटके, व्यापक पैमाने पर हुई तबाही

एजेंसी। काराकास

वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों ने व्यापक तबाही मचा दी। अब तक की जानकारी के अनुसार, इस प्राकृतिक हादसे में 164 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 971 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और बचाव कार्य जारी हैं। दुनिया भर से सहायता की पेशकश आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वेनेजुएला को हर संभव मदद देने की पेशकश की है। चीन, अमेरिका, इक्वाडोर, कतर, मैक्सिको और अल साल्वाडोर समेत कई देशों ने राहत एवं बचाव सहायता खेप की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार पहला भूकंप बुधवार शाम करीब 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के करीब 4.00 बजे) 7.1 तीव्रता का था। इसके ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। दोनों भूकंपों का केंद्र राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में स्थित तटीय शहर मोरोन के पास आए। भूकंप की गहराई मात्र

10 किलोमीटर होने के कारण इसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी रहा। सबसे अधिक नुकसान उत्तरी वेनेजुएला का तटीय राज्य ला गुएरा में हुआ है, जिसे सरकार ने "आपदा क्षेत्र" घोषित कर दिया है। दर्जनों इमारतें ढह गई हैं और कई इलाकों में संचार व्यवस्था बाधित होने से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी काराकस और उसके आसपास भी कई बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गईं। सरकार ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। राजधानी में बिजली और मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गए। सिमॉन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचने के कारण बंद करना पड़ा, जबकि मेट्रो सेवाएं और प्राकृतिक गैस आपूर्ति भी अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। स्कूलों में कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कुछ स्कूलों को राहत शिविरों में बदला जा रहा है। राहतकर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।

**सरकार का त्वरित जवाब और आपातकाल की घोषणाः** वेनेजुएला के आंतरिक मंत्री दियोसदादो काबेलो ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि कई भवन, घर और आवासीय ढांचे गिर गए हैं और सरकार अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, सिविल डिफेंस और अन्य आपदा राहत एजेंसियों को तत्काल सक्रिय कर दिया गया है। टेलीविजन फुटेज में कराकस में एक ढही हुई इमारत के मलबे के बीच राहतकर्मी लोगों की तलाश करते नजर आए। कई स्थानों पर परिजन अपने प्रियजनों के मलबे में फंसे होने की आशंका के बीच मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। इस बीच, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकालीन घोषणा लागू करने की बात कही है।

### पीएम मोदी ने जान गंवाने वालों के प्रति जताया शोक

**नई दिल्ली।** वेनेजुएला की राजधानी काराकास में दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें भारी जानमाल की हानि हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को इस तबाही में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से, वे वेनेजुएला सरकार और जनता, विशेषकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं तथा इस मुश्किल समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि काराकास में दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही हुई है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। भूकंप की तीव्रत रिक्टर पैमाने पर 7.5 और 7.2 मापी गई है।

## ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

### कैसे होगी भारतीय नागरिकों की पहचान?

भारत में जन्म-मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। 1969 से यह कानून लागू है। भारत के सभी राज्यों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बाद भी उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है। इसके पहले 1952 के प्रथम चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की गई थी। मतदाता सूची के माध्यम से 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का पंजीयन चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। यह पंजीयन चुनाव आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर करते थे। 1969 के बाद जन्म मृत्यु पंजीयन का कानून बनाया गया था। वही नागरिकता और उम्र का प्रमाण माना जाता था। पिछले वर्ष से चुनाव आयोग ने अपने ही बनाये गये मतदाता कार्ड को अमान्य बता दिया।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए नागरिकता के लिए जो पहचान के दस्तावेज जरूरी बताए थे, उसे भी सुप्रीम कोर्ट, विदेश मंत्रालय और सरकार के विभिन्न निर्णय में नकार दिया गया है। कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत के नागरिक हैं, इसको साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज है, इसका कोई उल्लेख ना तो चुनाव आयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने नागरिकता के प्रमाण स्वरूप कौन से दस्तावेज होंगे, इसका फैसला नहीं किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग की मतदाता सूची और मतदाता प्रमाण को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना।

आधार और पासपोर्ट भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर कौन सा प्रमाण पत्र है, जिसे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण माना जाए। इसको भारत सरकार भी नहीं बता पा रही है। ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान एवं अन्य देशों से आकर भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। विदेश से आने वालों को केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता का प्रमाण पत्र देता है। भारत में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जो आपके भारत में जन्म और नागरिक होने का प्रमाण माना जाए।

75 सालों बाद यह स्थिति पहली बार चुनाव आयोग के कारण देखने को मिल रही है। अब सब जगह से एक ही आवाज सुनने को मिल रही है, हम कैसे प्रमाणित करें, हम भारतीय नागरिक हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है, भारतीय नागरिक वही होगा, जो हिंदू हो, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो। उसे ही भारत के नागरिक होने का प्रमाण मान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सारे देश में अनिवार्य किया था। इसका एक ही उद्देश्य था जन्म के साथ ही भारतीय तथा उम्र नागरिकता प्रमाणित हो जाए। आधार कार्ड को भी जब अनिवार्य किया गया था, हर नागरिक और बच्चों का इसमें पंजीयन कराना था। इसमें आंखों की पुतलियां और हाथ के छापे भी लगवाए गए थे।

**सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक**
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

## संक्षिप्त समाचार

### इबोला के खतरे को देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए एअर सुविधा पोर्टल शुरू

**नई दिल्ली।** इबोला प्रभावित देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए एअर सुविधा पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है। अब यात्रियों को विमान से उतरने से पहले अनिवार्य सेल्फ डेकोरेशन फार्म ऑनलाइन भरना होगा। इससे पहले सारी प्रक्रिया कागजी फार्म के माध्यम से पूरी की जाती थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डायल द्वारा डीजी एचएस के सहयोग से एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी प्रवेश स्थानों पर इबोला सहित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करना है। यह उन्नत प्रणाली स्वास्थ्य, इमिग्रेशन और निगरानी एजेंसियों के बीच रियल-टाइम समन्वय को सक्षम बनाती है, जिससे संभावित जोखिम वाले यात्रियों की शीघ्र पहचान संभव हो सके। मंत्रालय ने कहा कि भारत की यात्रा करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले एअर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा । यह फॉर्म भारत आगमन से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन भरा जा सकता है और इसे समय पर पूरा करना सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है।

### लोकसभा अध्यक्ष बागियों की सांसदी पर जल्द लेंगे फैसला

#### दो-तिहाई बहुमत का नियम अहम

**नई दिल्ली।** लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों के दल-बदल मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसका भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। स्पीकर ने दोनों मूल पार्टियों और उनके बागी गुटों के प्रतिनिधिमंडलों से पहले ही मुलाकात कर ली है ताकि सभी पक्षों को सुना जा सके। संसद से जुड़े कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिया गया निर्णय कानूनी रूप से पूरी तरह सही हो, दल-बदल विरोधी कानून से जुड़े पुराने मामलों और मिसालों की भी गहन समीक्षा की जा रही है। टीएमसी के मामले में, पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में लोकसभा की 29 सीटें जीती थीं, जिनमें से एक सांसद के निधन के बाद फिलहाल एक सीट खाली है। पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत करते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया है। इन बागियों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है।

### हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक

**नई दिल्ली।** पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि यह दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिलाता है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक, यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। उन्होंने लिखा- आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी गइर थी, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाज सेवकों को गिरफ्तार किया गया व उन संस्थाओं पर हमला किया गया, जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। साथ ही उस दौर ने अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी दिखाया, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम सभी के लिए, हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसा भारत बनाएंगे, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे।

### गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित अलग-अलग समीक्षा बैठकों में तेलंगाना में 4,931 कि.मी., केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 2,035 कि.मी. और लद्दाख में 804 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि मीडिया रिपोर्टों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए प्राप्त फीडबैक और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के अधिकारियों और परियोजना ठेकेदारों से प्राप्त इनपुट के आधार पर ये समीक्षाएं की गईं। मंत्रालय के मुताबिक नितिन गडकरी ने इस बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं, रखरखाव गतिविधियों और सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने गुणवत्ता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। गडकरी ने अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को निगरानी तंत्र को मजबूत करने, कार्यों को समय पर पूरा करने और राजमार्ग गलियारों की स्थायित्व, आरामदायक यात्रा और दीर्घकालिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकियों और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा में सुधार के लिए सुव्यवस्थित सड़क अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना के सभी हिस्सों में मानसून की व्यापक तैयारियों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी जल निकासी प्रबंधन, ढलान स्थिरीकरण और संरक्षण कार्य तथा मौसम-संबंधी व्यवधानों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों की तैनाती सहित निवारक और शमन उपाय करने का निर्देश दिया।

### राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

**नई दिल्ली।** राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को राज्यसभा सदन में 10 नवनिर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में प्रवीण चक्रवर्ती, देबाशीष सामंतराय, सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायाला, भाष्यम राम कृष्ण, लिंगामनेनी रमेश, राजेश परमानंद शुक्ला, बैद्यनाथ राम, परिमल नथवानी तथा ताई टागक शामिल हैं। इनमें पांच सदस्यों ने हिंदी में, एक सदस्य ने अंग्रेजी में, एक सदस्य ने तमिल में तथा तीन सदस्यों ने तेलुगु में शपथ ली। शपथ लेने वाले सदस्यों में चार सदस्य आंध्र प्रदेश, दो सदस्य झारखंड तथा एक-एक सदस्य तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा से हैं। इस अवसर पर कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी, सदन के अन्य सदस्य, गणमान्य व्यक्ति तथा राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

### आपातकाल केवल इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लगाया गया थाः रविशंकर प्रसाद

**नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि आपातकाल केवल इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लगाया गया था। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पपत्रकार वार्ता में उन्होंने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उन्हें पूर्ण राहत नहीं मिली। जब यह घटनाक्रम हुआ, तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिशें शुरू हुईं और इसी क्रम में आपातकाल लगाया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात की जाती है, संविधान दिखाया जाता है। ऐसे में उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है 50 साल पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि वे जेपी आंदोलन के एक सेनानी थे । मीसा के तहत बंदी भी रहे और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया। इसलिए उस दौर की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से याद कर सकते हैं। जिस तरह जेल में अत्याचार किया गया, उस पर कई पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं।

### 'संविधान हत्या दिवस' पर उपराष्ट्रपति समेत केंद्रीय मंत्रियों ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय

एजेंसी। नई दिल्ली

'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं ने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपातकाल संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की कठिन परीक्षा का दौर था, जब नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई थीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया था। उन्होंने संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला गया और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों तथा नागरिकों को जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह दिवस लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सत्ता के अहंकार ने संविधान की आत्मा, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 'संविधान हत्या दिवस' का उद्देश्य इस घटना को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखना और भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसे आघात की पुनरावृत्ति रोकना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 25 जून 1975 वह दिन था जब सत्ता के अहंकार ने संविधान की आत्मा को कुचलते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया। उन्होंने कहा कि 'संविधान हत्या दिवस' संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के राष्ट्रीय दायित्व की याद दिलाता है।

# मॉनसूनः कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं आंधी-तूफान, 14 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत इस समय मौसम के कई अलग-अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक ओर जहां दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून बेहद मजबूत स्थिति में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के एक बड़े हिस्से को भिगो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 14 राज्यों के लिए आज यानी 25 जून को भारी से बहुत भारी बारिश और गंभीर स्तर के आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभावों का संकेत देता है।मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय दहानू, वर्धा, रायपुर, डालटनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है।

पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह कवर कर लिया है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के नए इलाकों में भी अपनी दस्तक दे दी है, जिससे इन राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है।

**दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उप्र :** दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आज का दिन राहत और थोड़ी आफत दोनों लेकर आया है। राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवातीय सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है, जिसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा पर दिखेगा। आज इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा (झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक) की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं या थंडरस्कॉल आ सकते हैं। आंधी के साथ ही गरज-चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, आईएमडी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे आंधी के समय खुली जगहों या पेड़ों के नीचे जाने से बचें।

**मध्य और पूर्वी भारत में मौसम का हाल :** बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और ओडिशा में गंभीर चेतावनी आज के मौसम की सबसे गंभीर चेतावनी मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों के लिए है, जहां मध्यम से गंभीर स्तर की आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

### अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दो विमान आमने-सामने आए, बड़ा हादसा टला

**अहमदाबाद।** अहमदाबाद हवाई अड्डे परन 'पार्किंग बे' की ओर जाते समय एअर इंडिया का एक विमान गलत दिशा में मुड़ गया, जिससे वह इंडिगो के एक विमान के सामने आ गया। हालांकि दोनों विमान एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रुक गए। सूत्रों ने बताया कि मुंबई जा रहा इंडिगो का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी एअर इंडिया का विमान गलत दिशा में मुड़ गया और वह उसी टैक्सीवे पर आ गया, जिस पर इंडिगो का विमान खड़ा था। सूत्रों के मुताबिक टैक्सीवे पर दोनों विमान समय रहते एक-दूसरे से करीब 200 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रुक गए। एअर इंडिया ने एक बयान में कहा कि हमें उस घटना की जानकारी है, जिसमें 24 जून को मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली हमारी एआई 2493 उड़ान लैंडिंग के बाद 'पार्किंग बे' की तरफ जाते समय अनजाने में गलत रास्ते पर मुड़ गई थी। विमानन कंपनी ने कहा कि विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसने बताया कि बाद में विमान को सुरक्षित रूप से 'पार्किंग बे' में ले जाया गया। एअर इंडिया ने कहा कि नियामक प्राधिकरण को मामले की जानकारी दे दी गई है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
( 9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

## संक्षिप्त समाचार

### गौतमपुरी में 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या

**नई दिल्ली।** उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र स्थित गौतमपुरी में बुधवार रात एक 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल नाबालिग को उसका चचेरा भाई अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब नौ बजे गौतमपुरी की गली नंबर-4 में चाकूबाजी की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल युवक को पहले ही उसके चचेरे भाई द्वारा जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल ले जाया जा चुका है। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 17 वर्षीय लकी कुमार के रूप में हुई है। वह गौतमपुरी के रहने वाले है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामले में सीलमपुर थाने में एफआईआर संख्या 247/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल आरोपितों की पहचान कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

### उपराज्यपाल ने संजय झील के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के कामों का लिया जायजा

**नई दिल्ली।** दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा करते हुए वहां चल रहे जीर्णोद्धार और कायाकल्प के कामों का जायजा लिया। मौके पर निरीक्षण के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को 52 एकड़ में फैली झील और इसके आस-पास के 165 एकड़ के संरक्षित जंगल को फिर से जीवंत करने की चरणबद्ध कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी।उपराज्यपाल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण 'ब्लू-ग्रीन' (जल और हरियाली वाले) क्षेत्र को हर मौसम में इस्तेमाल लायक और साफ-सुथरी मनोरंजक जगह बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने डल्लूपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को संचालित पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि झील को बचाने और उसे फिर से जीवंत करने के लिए लगातार खरपतवार हटाने, काई (शैवाल) साफ करने और जियो-टेक्सटाइल तकनीक का इस्तेमाल करके तटबंधों की ढलानों को मजबूत करने का काम पहले से ही चल रहा है। आने वाले चरणों में रुके हुए पानी के बहाव को ठीक करने, भूजल रिचार्ज को बढ़ाने के लिए बायो-स्वेल्स लगाने, बायो-रेमेडिएशन के उपाय करने और पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एरेटर और फव्वारे लगाने पर ध्यान दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि इसके अलावा 5,000 देसी पेड़ लगाकर इलाके की पारिस्थितिक जैव-विविधता को समृद्ध किया जाएगा। हम संजय झील को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

### मालदा हिंसा मामले में एनआईए ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान हुई हिंसा, सड़क अवरोध और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मालदा के मोथबाड़ी क्षेत्र के स्थानीय राजनीतिक नेता सायेम चौधरी उर्फ बाबू चौधरी के रूप में हुई है।एनआईए ने गुरुवार को बताया कि सायेम चौधरी को कोलकाता स्थित एजेंसी के शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 30 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।एजेंसी के अनुसार, वह विधानसभा चुनाव से पहले मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हुए भीड़ प्रदर्शन, हिंसा और न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने से जुड़े एक दर्जन से अधिक मामलों की जांच कर रही है।जांच में सामने आया कि सायेम चौधरी एक अप्रैल को बीडीओ कार्यालय ब्लॉक-द्वितीय में न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से रोककर रखने की घटना में प्रमुख आरोपित है। वह उस भीड़ का हिस्सा था जिसने कानून-व्यवस्था बाधित की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस हमले में नौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे।एनआईए के अनुसार, आरोपित ने घटना से एक दिन पहले बीडीओ कार्यालय के सामने भाषण देकर लोगों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाया था। उसने अन्य सह-आरोपितों के साथ मिलकर साजिश रची और एसआईआर अभियान के दौरान हिंसा, धमकी तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। एनआईए ने कहा कि अप्रैल में मालदा में हुई व्यापक चुनाव पूर्व हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और सभी आरोपितों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इन मामलों की जांच शुरू की थी। न्यायालय ने अप्रैल में हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था।

### भारत ने सिंगापुर को बंगनापल्ली आमों का पहला व्यावसायिक समुद्री खेप किया निर्यात

**नई दिल्ली।** ताजे फलों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आंध्र प्रदेश से 5 मीट्रिक टन बंगनापल्ली आमों की पहली व्यावसायिक समुद्री खेप सिंगापुर को सफलतापूर्वक भेजी है। यह भारतीय बागवानी उत्पादों के किफायती और टिकाऊ निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि बंगनापल्ली आमों के इस निर्यात खेप से किसानों को काफी आर्थिक फ़ायदा भी हुआ। मंत्रालय ने कहा कि जहां घरेलू बाजार में कीमतें 25 रुपये से 26 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थीं वहीं, निर्यात खेप से लगभग 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कमाई हुई। इससे किसानों को मिलने वाली आमदनी लगभग दोगुनी हो गई और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिला।मंत्रालय ने कहा कि इस खेप में मेसर्स ओसम फूड सॉल्यूशंस एलएलपी द्वारा निर्यात किए गए 5 मीट्रिक टन (एमटी) बंगनापल्ली आम शामिल थे। यह खेप 11 जून को भेजी गई थी, जो 24 जून को सिंगापुर पहुंची। एपीडा का यह कदम समुद्र के रास्ते कम लागत वाले फल निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।मंत्रालय ने कहा, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर (सीआईएसएच), लखनऊ के साथ मिलकर भारत से सिंगापुर तक प्रीमियम बंगनपल्ली आमों के पहले कमर्शियल समुद्री शिपमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है।" वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा ने सिंगापुर को बंगानापल्ली आमों की पहली सफल व्यावसायिक समुद्री खेप भेजी गई, यह एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि पहले आम मुख्य रूप से हवाई मार्ग से भेजे जाते थे। यह कदम समुद्र के रास्ते कम लागत वाले फल निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

# डीजे से गाना बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद बना खूनी संघर्ष, हत्या के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में स्थित ओएच विलेज (लॉज एंड बार) में गाना बदलने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस मामले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए यह पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित घटना के बाद फरार हो गए थे और उनके संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं था। हालांकि, क्राइम ब्रांच की डब्ल्यूआर-1 टीम ने तकनीकी निगरानी, खुफिया जानकारी और लगातार प्रयासों के बल पर मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।क्राइम ब्रांच के अनुसार, 17 और 18 जून की दरम्यानी रात शाहबाद दौलतपुर स्थित ओएच विलेज (लॉज एंड बार) में दो युवकों पर चाकुओं से हमला किया गया था। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में 18 जून को शाहबाद डेयरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और 3(5) के तहत एफआईआर संख्या 350/2026 दर्ज की गई थी। इलाज के दौरान 23 जून को एक घायल की मौत हो जाने पर मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस भी जोड़ दी गई।

**सुराग नहीं था, फिर भी आरोपितों तक पहुंची पुलिस:** मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की डब्ल्यूआर-1 यूनिट को जांच में लगाया गया। पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपित लगातार ठिकाने बदल रहे थे। टीम ने मानव स्रोतों और तकनीकी इनपुट पर लगातार काम किया। हेड कांस्टेबल पवन कुमार को आरोपितों की गतिविधियों और संभावित ठिकाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली। वहीं हेड कांस्टेबल हरजीत सिंह ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपितों की लोकेशन, आवाजाही और संपर्कों का विश्लेषण किया। इससे जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिली और आरोपितों तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ।क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा के निर्देशन में एसीपी राज कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के नेतृत्व में टीम गठित की गई। 24 जून को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर रानी बाग स्थित महावीर अस्पताल के पास निगरानी बढ़ाई गई। कुछ समय बाद दो संदिग्ध वहां आते दिखाई दिए। मुखबिर के इशारे पर पुलिस टीम ने दोनों का पीछा कर उन्हें दबोच लिया।गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक निवासी 18 वर्षीय अभिषेक और 18 वर्षीय अश्विन के रूप में हुई। दोनों की उम्र 19 वर्ष से कम है और वे एक ही इलाके के रहने वाले हैं।पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने बताया कि घटना वाली रात वे अपने कुछ साथियों के साथ ओएच विलेज में हुक्का पीने गए थे। वहां उन्होंने डीजे ऑपरेटर से गाना बदलने के लिए कहा, लेकिन डीजे ने उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया। आरोपितों का दावा है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट के बाद आरोपी वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित अपने इलाके मंगोलपुरी लौटे और वहां से अपने अन्य साथियों को साथ लेकर चाकुओं से लैस होकर दोबारा ओएच विलेज पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया, जिन्हें वे अपने साथ हुई मारपीट के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। आरोप है कि दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। क्राइम ब्रांच का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपितों की भूमिका की पुष्टि हो चुकी है। मामले में अन्य साथियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने, फरार आरोपितों की पहचान करने और हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

# केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को यहां केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और राज्य में जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न मुद्दों पर विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कीआधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा लापरवाही को कतई बर्दाश्त न किया जाए। साथ ही गांव-गांव अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों तथा जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

## आपातकाल के बारे में नई पीढ़ी को पता होना चाहिए : सूद

लोकतंत्र की शान

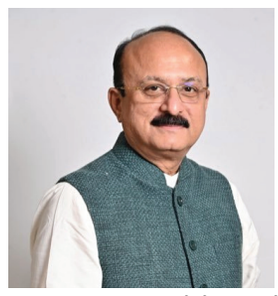

**नई दिल्ली।** दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में 'आपातकाल' पर अध्याय जोड़े जाने पर गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है, "अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल में क्या अंतर है? नई पीढ़ी को यह सब पता होना चाहिए।"मंत्री सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीईआरटी ने आपातकाल के दौरान लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को किस प्रकार से छीना गया, उसको एनसीईआरटी ने नई पीढ़ी को बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह सब पता होना चाहिए, ताकि कोई भी फिर से ऐसी कोशिश न कर सकें। मंत्री सूद ने इससे पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। सत्ता बचाने के लिए लगाए गए आपातकाल ने देशवासियों के मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा आघात किया। उन्होंने कहा कि 'संविधान हत्या दिवस' पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और नागरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनका साहस और त्याग सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा।उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 1975-77 के आपातकाल को शामिल किया है। पुस्तक में मौलिक अधिकारों के निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और जयप्रकाश नारायण आंदोलन का जिक्र है।

## आआपा ने निगम की बैठक में दिल्ली के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मुख्यालय सिविक सेंटर में गुरुवार को सदन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी (आआपा) के सभी पार्षदों ने दिल्ली में बढ़ते अग्निकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया साथ ही अयोध्या राम मंदिर में कथित तौर पर हुई चोरी का मुद्दा भी उठाया।आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता और दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आज एमसीडी सदन बैठक में दिल्ली में लगातार हो रही इमारत ध्वस्त होने की घटनाओं, भीषण अग्निकांडों, मानसून में जलभराव और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुई चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की।अंकुश नारंग ने कहा कि सरकार जनता के सभी सवालों से भागती है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने हादसों पर जवाब नहीं दिया। जलभराव पर जवाब नहीं और राम मंदिर के चंदे में हुई चोरी पर भी जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी जवाबदेही की बात आती है, सरकार सदन छोड़कर भाग जाती है और लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोंटती है। नारंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा से खिलवाड़, जवाबदेही से पलायन और सच पर पर्दा डालने की राजनीति कर रही है।

## दिल्ली ने साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया : डॉ. पंकज कुमार सिंह

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सरकारी डेटा की सुरक्षा केवल एक तकनीकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारी जवाबदेही भी है। उन्होंने कहा कि हम सरकारी डेटा और नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा के लिए अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं।यह बातें मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में 'राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने' विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही। इस कार्यशाला का आयोजन दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से किया।मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर खतरों की निरंतर बदलती प्रकृति को देखते हुए हमें सदैव सतर्क रहना होगा, अपनी साइबर क्षमता को और मजबूत करना होगा तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी प्रणालियों में साइबर लचीलापन को सुदृढ़ करना, विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना तथा उभरते साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है।मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में डेटा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधी लगातार अधिक उन्नत और जटिल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। ऐसे में सरकारों के लिए निरंतर सतर्क रहना और साइबर सुरक्षा तंत्र को लगातार मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।मंत्री ने कहा कि संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा निर्बाध जनसेवा सुनिश्चित करने और डिजिटल शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी विभागों से साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम मानकों को अपनाने तथा सरकारी संस्थानों में साइबर जागरूकता की संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया।कार्यशाला में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया तंत्र, डेटा गोपनीयता, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा साइबर जोखिम प्रबंधन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, सुरक्षा ऑडिट, साइबर जागरूकता तथा विभिन्न सरकारी विभागों में मजबूत सुरक्षा ढांचे को अपनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।कार्यशाला का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि दिल्ली के साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सतत सहयोग, नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। कार्यशाला से प्राप्त सुझाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक व्यापक एवं सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढांचे के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

## उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी बीच उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप भी जारी रहने की संभावना है।मौसमक विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 26 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर-शाम के समय तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 39-41 डिग्री सेल्सियस और 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 27 और 28 जून को भी यही स्थित रहने का अनुमान है।उल्लेखनीय है कि राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर-शाम के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया था। फिलहाल, राजधानी के निवासियों ने आज के मौसम में गर्माहट महसूस की है।मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम अधिकारियों के पूर्वानुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ इस सप्ताह पश्चिमी तट, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना है। वहीं, अगले 3-4 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अगले 2 दिनों में बिहार और झारखंड में लू चलने की संभावना है।उत्तर-पश्चिम भारत के 25-30 जून और एक जुलाई के दौरान केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में, 30 जून से एक जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 29 जून से एक जुलाई के दौरान उत्तराखंड में व्यापक से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 30 जून से 1 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी व्यापक बारिश होने की चेतावनी दी गई है।इस दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर-पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जगहों पर अगले पांच दिनों के दौरान भारी और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। इन क्षेत्रों में अगले छह दिनों के दौरान तूफानी हवाएं चलने के आसार हैं जिनकी रफ्तार 40 से लेकर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।बिहार में कुछ जगहों पर 25 जून, 25-26 जून के दौरान झारखंड में और 25-28 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की बहुत संभावना है। साथ ही 25-27 जून के दौरान कुछ जगहों पर भीषण लू की स्थिति भी हो सकती है। उत्तर-पश्चिम भारत में 28 तारीख तक अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और उसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है जबकि मध्य भारत में 28 तारीख तक अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। देश के शेष हिस्सों में एक जुलाई तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।

## आवासीय समिति धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत गुरुवार को गाजियाबाद और दिल्ली स्थित कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई संदीप सिंह श्रस्थ प्रोपबिल्ड प्रा. लि. के प्रवर्तकों तथा सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में की गई। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जांच में पता चला है कि आरोपियों ने समिति के सदस्यों को पुनर्विकास परियोजना के तहत आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर स्थित लगभग 41,544 वर्गमीटर भूमि पर उनके अधिकार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बाद में विकास अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए समिति की भूमि और फ्लैट तीसरे पक्ष को बेच दिए गए, जिससे अवैध आय अर्जित की गई। ईडी की तलाशी का उद्देश्य कथित धनशोधन से जुड़े साक्ष्य जुटाना है। मामले की जांच जारी है।

## संक्षिप्त समाचार

### बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई उड़ान, लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करेगी भारत सरकार

**लोकतंत्र की शान , लखनऊ** : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को लखनऊ स्थित योजना भवन के वैचारिकी सभागार में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश सबसे अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, विकसित भारत का लक्ष्य उतनी ही शीघ्रता से साकार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी समन्वय तथा साझा प्रयासों से इस राष्ट्रीय संकल्प को अवश्य पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कृषि, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, लेकिन बदलते समय की चुनौतियों के बीच विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र में गंभीर मंथन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, ताकि कृषि को अधिक उत्पादक, लाभकारी, जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ बनाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।

### भाजपा जन कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हुआ भव्य स्वागत समारोह

**हसनपुर लोकतंत्र की शान सतीश चंद्र राणा,** भाजपा जन कल्याण मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भीष्म सिंह खड़गवंशी का संगठन के कार्यालय पर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का विश्वास व्यक्त किया। इस मोके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ ओपी गोला, जिलाध्यक्ष अमरोहा रुमाल सिंह सैनी, वीर सिंह, शिवराज सिंह, उदल सिंह, महेंद्र सिंह खड़गवंशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हुए संगठन की मजबूती और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़गवंशी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, संगठन विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम सफलता पूर्वक में संपन्न हुआ। अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन की नीतियों एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।

### मत्स्य पालन पट्टा आवंटन के लिए नीलामी शिविर 8 जुलाई को

**लोकतंत्र की शान , बांदा**। जिला सूचना कार्यालय बांदा से मिली जानकारी के अनुसार, तहसील बबेरू जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में स्थित तालाबों, पोखरों, जलाशयों और जल प्रणालियों के 10 वर्षीय मत्स्य पालन एवं जल-जात पदार्थों के उत्पादन हेतु पट्टा आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आगामी 08 जुलाई 2026 दिन बुधवार) को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर बबेरू तहसील कार्यालय के सभागार में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक नायब तहसीलदार (नीलामी अधिकारी) की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इच्छुक आवेदकों से प्रार्थना पत्र एकत्रित कर विकास खण्डवार पात्रता सूची तैयार की जाएगी। यदि एक ही तालाब के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन आते हैं, तो पारदर्शी तरीके से नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदकों को आरक्षित बोली की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में पहले जमा करनी होगी। छोटे तालाब (2.000 हेक्टेयर से कम) इनकी न्यूनतम नीलामी दर 5,000 प्रति हेक्टेयर तय की गई है। इन तालाबों के आवंटन में मछुवा समुदाय को प्रथम वरीयता दी जाएगी। बड़े तालाब (2.000 हेक्टेयर या उससे अधिक) इनकी नीलामी केवल पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के बीच होगी, जिसकी न्यूनतम दर 10,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।

# मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पांच लोग घायल

लोकतंत्र की शान / सतीश चंद्र राणा

**हसनपुर**: हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे और लोहे की रॉड चल गईं। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, गांव में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी और गाली-गलौज हुई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने घरों से लाठी-डंडे तथा लोहे की रॉड लेकर आमने-सामने आ गए। इसके बाद जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष से गौरव पुत्र डालचंद, मोनी पत्नी डालचंद तथा निगम पुत्र धर्मवीर घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष से सर्वेश पुत्र अशोक और सुनीता पत्नी कुंवरपाल को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया

। कोतवाली प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## रामपुरः युवक को बंधक बनाकर मारपीट, नगदी और बाइक लूटने का आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

लोकतंत्र की शान/ मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

**रामपुर। उत्तर प्रदेश/** जनपद रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में एक युवक को कथित रूप से बंधक बनाकर मारपीट करने, जातिसूचक शब्द कहने, नगदी छीनने तथा मोटरसाइकिल लूट लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रामपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बरेली जनपद के थाना शीशगढ़ क्षेत्र के ग्राम शीशगढ़ देहात निवासी सोनू पुत्र सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि वह 6 जून 2026 को सुबह करीब 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मिलक की ओर से वापस लौट रहा था। मिलक बाईपास के पास उसे प्रदीप कुमार यादव और उसके चार साथियों ने रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की तथा उसे जमीन पर गिरा दिया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन

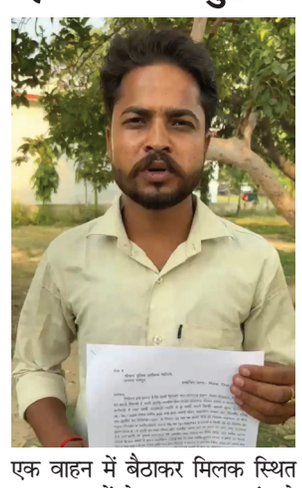

एक वाहन में बैठाकर मिलक स्थित एक मकान में ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन वीडियो भी बनाई। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उसकी जाति पूछकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसके पास से 18 हजार रुपये छीन लिए। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में ले ली।

## स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्यप्रद व स्वच्छ आहार-विहार आवश्यक : मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

**गोरखपुर**। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छ आहार-विहार का होना आवश्यक है। कुपोषण से मुक्ति के लिए जरूरी है कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। समाजहित में यह कार्य अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिलने से स्वस्थ बच्चे समृद्ध समाज का आधार बनेंगे। सीएम योगी गुरुवार शाम गोरखपुर में राज्य सरकार के सहयोग से बने, एक लाख बच्चों के लिए भोजन क्षमता वाले अक्षयपात्र फाउंडेशन के केंद्रीयकृत रसोईघर के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के मिड डे मील के लिए अक्षयपात्र फाउंडेशन की तरफ से

भोजन निर्माण में स्वच्छता, पोषण और गुणवत्ता का जो ध्यान रखा जाता है, वह सबके लिए सीखने लायक है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर में अक्षयपात्र फाउंडेशन के रसोईघर पहले से संचालित हैं। अब सरकार के सहयोग से गोरखपुर में केंद्रीयकृत रसोईघर का निर्माण कर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। नए शैक्षिक सत्र में 50 हजार से अधिक स्कूली बच्चों को फिर कुछ समय में ही 1 लाख बच्चों को यहां से गर्मागर्म भोजन मेन्यू के हिसाब से प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट सरकार उपलब्ध कराती है। बेहतर ढंग से भोजन बनाने और वितरण का कार्य अक्षयपात्र की तरफ से किया जा रहा है।

## बिटैक में लाइबा नूर ने किया टॉप, 86.31 प्रतिशत अंकों के साथ लहराया परचम

» आठवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन, संस्थान में खुशी की लहर

लोकतंत्र की शान/ खिज़र अहमद

**नजीबाबाद**। बुंदकी रोड स्थित एसआईसीसी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (बोटेक) के आठवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग की मेधावी छात्रा लाइबा नूर ने 86.31 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अरमान अंसारी ने 86.00 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा देवांश अप्पवाल ने 85.69 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। अन्य विभागों में भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सिविल अभियांत्रिकी विभाग में हंसराज गौतम ने 84.90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में तेजेंद्र प्रताप ने 83.54 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग में सौरभ दीप ने 82.77 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया। सफल विद्यार्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं कठिन परिश्रम को दिया। विद्यार्थियों

का कहना है कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के कारण ही यह सफलता संभव हो सकी। शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, निरंतर अध्ययन और मेहनत का यह परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी।

## सिरसी में सबील-ए-हुसैन का एहतेमाम, मुसाहिब हुसैन नक़वी व कम्बर अब्बास नक़वी रहे पेश-पेश

लोकतंत्र की शान

**संभल/सिरसी**। मोहर्रमुल हराम के ग़मगीन माहौल में जहां पूरी दुनिया के अज़ादार शोहदाए कर्बला को ख़िराज-ए-अकीदत पेश कर रहे हैं, वहीं कस्बा सिरसी के इमामबाड़ा इमाम रज़ा (अ.स.) में नगर पंचायत प्रत्याशी मुसाहिब हुसैन नक़वी एवं उनके भाई, युवा समाजसेवी कम्बर अब्बास नक़वी की ओर से दूध की सबील का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अज़ादारों, बुजुर्गों, युवाओं और राहगीरों ने सबील से तबर्रुक हासिल किया। मोहर्रम के दिनों में लगाई जाने वाली सबीलें कर्बला के उस अज़ीम पैग़ाम की याद दिलाती हैं, जब इमाम हुसैन (अ.स.) और उनके वफ़ादार साथियों ने दीन-ए-इस्लाम और इंसानियत की हिफ़ाज़त के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी थी। उन्हीं कुर्बानियों की याद में मुसाहिब हुसैन नक़वी और कम्बर अब्बास नक़वी ने अज़ादारों की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझते हुए सबील का आयोजन किया। सबील पर दिनभर अज़ादारों का आना-जाना लगा रहा। दोनों भाइयों ने स्वयं मौजूद रहकर लोगों का इस्तक़बाल किया और खिदमत-ए-अज़ादार का फ़र्ज़ निभाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन (अ.स.)

की ज़िंदगी हमें इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे, सब्र और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का सबक देती है। मोहर्रम केवल ग़म मनाने का महीना नहीं, बल्कि इंसानियत और खिदमत का पैग़ाम आम करने का भी महीना है। क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं अज़ादारों ने नक़वी बंधुओं की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुसाहिब हुसैन नक़वी और कम्बर अब्बास नक़वी हमेशा सामाजिक, धार्मिक और जनहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मोहर्रम के पवित्र दिनों में अज़ादारों के लिए दूध की सबील लगाकर उन्होंने अहलेबैत (अ.स.) से अपनी मोहब्बत और अकीदत का खूबसूरत इज़हार किया है। कार्यक्रम के दौरान इमाम हुसैन (अ.स.) और शोहदाए कर्बला की कुर्बानियों को याद किया गया तथा उनकी शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाने पर ज़ोर दिया गया। सबील पर मौजूद लोगों ने आयोजनकर्ताओं के लिए दुआएं कीं और इस नेक कार्य को समाज में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत को मज़बूत करने वाला कदम बताया। मोहर्रम के इन ग़मगीन दिनों में इमामबाड़ा इमाम रज़ा (अ.स.) में आयोजित यह सबील-ए-हुसैन न सिर्फ़ अज़ादारों की खिदमत का ज़रिया बनी, बल्कि इमाम हुसैन (अ.स.) के पैग़ाम-ए-इंसानियत को आम करने का भी बेहतरीन माध्यम साबित हुई।

## लखनऊ अग्नि कांड पर श्रद्धांजलि अर्पित करते महाकाल भक्त मण्डल ने

लोकतंत्र की शान/ खिज़र अहमद

**नजीबाबाद**। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुई दर्दनाक अग्नि दुर्घटना में कई मासूम बच्चों और नागरिकों की असामयिक मृत्यु पर महाकाल भक्त मंडल ने जताया दुख। नगर के मौहल्ला मकबरा स्थित गीता भवन

मंदिर में महाकाल भक्त मंडल द्वारा लखनऊ के अलीगंज में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। इस घटनाक्रम में कई छात्र-छात्राओं की मृत्यु हो गई और कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए। महाकाल भक्त मंडल ने इस घटना को अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक बताया। महाकाल भक्त मंडल ने ईश्वर से प्रार्थना कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। महाकाल भक्त मंडल ने इस दुःखद हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएँ व्यक्त की एवं ईश्वर से प्रार्थना की शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महाकाल भक्त मंडल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की । शोकसभा में पंडित भोला शंकर शास्त्री, सौरभ कुमार, सभासद पवन एडवोकेट, अभिनव अग्रवाल एडवोकेट, देवेंद्र प्रजापति, आशुतोष टॉक, रोहित कुमार, आदित्य, सागर, ऋषभ, आकाश, तरुण, लक्ष्मण, प्रदीप आदि रहे।

## डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक हैः हरीश गंगवार

लोकतंत्र की शान/ मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

**रामपुर /उत्तर प्रदेश/** रामपुर में"डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प, भाजपा जिला कार्यालय पर बैठक आयोजित" भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती स्मरण पक्ष (23 जून से 6 जुलाई) के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती स्मरण पक्ष केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यक्रमों की प्रभावी तैयारी एवं अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। गंगवार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की अवधारणा को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370

हटाकर उनके सपनों को साकार किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि स्मरण पक्ष के अंतर्गत बूथ स्तर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करें। अपने संबोधन में हरीश गंगवार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें तथा संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ सफल बनाएं। जिला प्रभारी राजा वर्मा ने बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले पुष्पांजलि कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मेलन, छात्र सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान एवं अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई। साथ ही सभी मंडलों एवं बूथों पर कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

## भाजपा में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइकः पूरन लाल लोधी ब्रज क्षेत्र के नए अध्यक्ष, दुर्विजय सिंह बने प्रदेश उपाध्यक्ष

लोकतंत्र की शान

**(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा)**, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और संगठन विस्तार की तैयारियों के बीच बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए ब्रज क्षेत्र में नेतृत्व परिवर्तन का अहम फैसला लिया है। पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता पूरन लाल लोधी को ब्रज क्षेत्र का नया क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह को पदोन्नति देकर प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के इस फैसले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने तथा चुनावी तैयारियों को धार देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए हमेशा से राजनीतिक

पूरनलाल लोधी

दुर्ग विजय सिंह

दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं, जहां पार्टी की मजबूत पकड़ बनाए रखने और उसे और विस्तार देने के लिए लगातार संगठनात्मक गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं। ऐसे में पूरन लाल लोधी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी का बड़ा और रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है।

**जमीनी कार्यकर्ता से क्षेत्रीय अध्यक्ष तक का सफर**-पूरन लाल लोधी लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र में भाजपा संगठन को नई गति और ऊर्जा मिलेगी तथा पार्टी की पहुंच गांव-गांव और घर-घर तक और मजबूत होगी।

**दुर्विजय सिंह को मिला अनुभव का सम्मान**-वहीं, ब्रज क्षेत्र के निवर्तमान अध्यक्ष दुर्विजय सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना पार्टी द्वारा उनके संगठनात्मक कौशल और कार्यशैली पर जताए गए भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है। उनके कार्यकाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए। संगठन में उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन्हें प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

## संक्षिप्त समाचार

### प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा, पिता पर गंभीर आरोप, मर्जी से घर छोड़ की शादी

**लोकतंत्र की शानः हाजीपुर।** वैशाली जिले के हाजीपुर से एक प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और हाजीपुर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जोड़े का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़कर शादी की है। लड़की की पहचान पोखरा मोहल्ला, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी पवन सिंह की बेटी संध्या सिंह (22) के रूप में हुई है। लड़के ने अपनी पहचान छोटी यूसुफपुर निवासी जितेंद्र कुमार का बेटा आदित्य कुमार (25) के रूप में बताई है। दोनों ने अपनी मर्जी से घर छोड़कर शादी की है और अब वैशाली पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वीडियो में संध्या ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनकी तलाश की जा रही है। उसने कहा कि वह और आदित्य पिछले तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे। जब उसके पिता ने उसकी शादी के लिए लड़के देखने शुरू किए, तो उसने उन्हें आदित्य के बारे में बताया और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। संध्या के अनुसार, यह बात सुनते ही उसके पिता ने उसे कथित तौर पर बुरी तरह पीटा और जहर देने की धमकी दी। इसके बाद उसने आदित्य को सूचित किया कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं और उसे घर से निकलने में मदद मांगी। संध्या ने यूपीआई के माध्यम से आदित्य को कुछ पैसे भेजे और फिर खाली हाथ अपने घर से निकल गई। अब दोनों ने शादी कर ली है और साथ रह रहे हैं। संध्या ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे घर छोड़ने में न तो उसके परिवार का और न ही आदित्य के परिवार का कोई हाथ है। उसने अपनी मर्जी से आदित्य के साथ शादी की है। लड़की ने प्रशासन से अपील की है कि यदि लड़के के परिवार को कोई भी नुकसान पहुँचता है, तो उसके लिए केवल उसके पिता जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष सिकन्दर कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

### पुलिस का हुड़दंगियों से निपटने को मॉकड्रिल, मोहर्रम से पहले वाटर कैनन चली, आंसू गैस के गोले दागे गए

**लोकतंत्र की शानः हाजीपुर।** वैशाली पुलिस ने मोहर्रम पर्व के दौरान हुड़दंगियों से निपटने की तैयारी में हाजीपुर पुलिस लाइन में एक रियलिस्टिक मॉकड्रिल का आयोजन किया।

पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर हुए इस अभ्यास में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अभ्यास के दौरान, दंगाइयों की भीड़ का दृश्य बनाया गया। पुलिस बल ने पहले लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। स्थिति बेकाबू होने पर वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार की गई, जिसके बाद आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान जवानों को त्वरित कार्रवाई और समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया। मॉकड्रिल के बाद, एसपी शुभांक मिश्रा ने सभी थानाध्यक्षों को मोहर्रम के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए कि वह केवल जुलूस तक ही सीमित रहे। एसपी ने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने यह भी साफ किया कि त्योहार के दौरान उपद्रव फैलाने, अफवाहें फैलाने या जबरन चंदा वसूली करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को तुरंत ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाएगा। वैशाली पुलिस ने जिलेवासियों से मोहर्रम का त्योहार गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है।

### पप्पू सहनी एनकाउंटर मामला,मुकेश सहनी ने आंदोलन की चेतावनी दी

**लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर।** मुजफ्फरपुर में वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे। इन्होंने पप्पू सहनी एनकाउंटर और भोजपुर एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार सरकार व पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यदि पप्पू सहनी फेक एनकाउंटर के आरोपितों की गिरफ्तारी एक महीने के अंदर नहीं हुई, तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन और चक्का जाम करेगी। वहीं भोजपुर एनकाउंटर मामले में उन्होंने कहा कि यदि डीएसपी राजेश शर्मा पर पहले हुई शिकायतों में कार्रवाई की गई होती, तो भोजपुर जैसी घटना नहीं होती। मुकेश सहनी ने कहा है कि ये सरकार फर्जी है। मुकेश सहनी ने कहा कि चार महीने बीत जाने के बावजूद पप्पू सहनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। पुलिस अब तक दोषियों तक नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर आने के दौरान वह पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनकी पीड़ा को करीब से समझा है। उन्होंने कहा, "हम मुजफ्फरपुर के एसएसपी को एक महीने का समय दे रहे हैं। यदि इस अवधि में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वीआईपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और सड़क जाम किया जाएगा।" प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में हत्या और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने अपने समाज के लोगों से एकजुट रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। भोजपुर जिले में हुए चर्चित एनकाउंटर का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता और उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि अंतिम न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनकाउंटर में शामिल डीएसपी राजेश शर्मा के खिलाफ पहले भी गंभीर आरोप सामने आए थे। यदि उन मामलों में समय रहते कार्रवाई की जाती तो भोजपुर की घटना नहीं होती। मुकेश सहनी ने कहा, "जिस अधिकारी पर सवाल उठ रहे थे, उस पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उसे प्रमोशन देकर आगे बढ़ा दिया। यदि समय रहते जवाबदेही तय की गई होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती।"

### शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, दुल्हन के मामा की मौत, परिजन ने साजिश की जताई आशंका

**लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर।** मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। गोली लगने से दुल्हन के मामा की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुसहरी निवासी रंजीत साहनी (32) के रूप में हुई है। दुल्हन का सगा मामा था। घटना करजा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, भटौना गांव निवासी शंभू सहनी की भतीजी की शादी थी। बारात आने के बाद द्वारपूजा सहित अन्य रस्में चल रही थी। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक गोली रंजीत साहनी को लगी। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिजन ने आरोप लगाया है कि किसी ने जानबूझकर गोली चलाई है। सूचना मिलते ही करजा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गांव के लोगों और समारोह में मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। थानेदार परमहंस कुमार ने बताया कि पुलिस को गोली लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है।

# स्मृति सौरभम् 2026 : नई मंज़िलों की ओर बढ़ते कदमों को भावभीनी विदाई

लोकतंत्र की शान

**वैशालीः** डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, वैशाली के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के सम्मान में "स्मृति सौरभम् 2026" फेयरवेल समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. समित तिवारी, प्रतिकुलपति डॉ. बसंत सिंह, कुलसचिव डॉ. ब्रिजेश सिंह, विभिन्न संकायों के डीन एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती श्वेता सिन्हा के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में कुलसचिव डॉ. ब्रिजेश सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सतत सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। प्रतिकुलपति डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि चुनौतियाँ ही व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती हैं तथा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी हैं। कुलपति डॉ. समित तिवारी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि फेयरवेल किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि नई संभावनाओं और अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के मूल्यों को आत्मसात करते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का प्रभावी मंच संचालन ऋषु कुमारी एवं स्नेहप्रिया द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत जूही, तनु प्रिया एवं साक्षी ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया, वहीं सोनाली मैम द्वारा प्रस्तुत फेयरवेल गीत ने समारोह को भावनात्मक रंगों से सराबोर कर दिया। समारोह की सफलता में कंप्यूटर साइंस विभाग के दीपक सिंह, तौकीर अख्तर, डॉ. नादिर कमाल, तनु पांडेय, सौरव सिंह एवं अमित कुँवर सहित समस्त शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोजन एवं व्यवस्थाओं में विभाग के विद्यार्थियों अविनाश, आयुष एवं चंदन ने विशेष भूमिका निभाई। उत्साह, उमंग, भावनाओं और सुनहरी यादों से परिपूर्ण यह फेयरवेल समारोह विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया तथा उनके जीवन के नए अध्याय की प्रेरणादायी शुरुआत का साक्षी बना।

## बैद्यबाटी नगरपालिका के कंज़र्वेंसी और जलापूर्ति विभाग के मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 100 रुपये की बढ़ोतरी : दिलीप सिंह

लोकतंत्र की शानः मोहम्मद शबीब आलम

**हुगलीः** चापदानी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह ने नगरपालिका मजदूरों की समस्याओं को सुनकर उनके समर्थन में खड़े होते हुए वर्षों से मिल रही कम मजदूरी में 100 रुपये की वृद्धि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज सुबह बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर विधायक के पास पहुंचे थे। दिलीप सिंह ने बताया कि बैद्यबाटी नगरपालिका के कंज़र्वेंसी और जलापूर्ति विभाग के मजदूर लंबे समय से मात्र 170 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम कर रहे थे। कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैंने मजदूरों से कहा था कि पहले इस मुद्दे को नगरपालिका प्रशासन के सामने उठाएं। जब वे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन में उतरे, तब उनकी दैनिक मजदूरी 170 रुपये से बढ़ाकर 270 रुपये कर दी गई।

## सहयोग शिविर, आरटीपीएस एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

लोकतंत्र की शानः मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता

**सहरसाः** जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने गुरुवार को गूगल मीट के माध्यम से आयोजित समीक्षात्मक बैठक में सहयोग शिविर हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति, लोक सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रगति तथा संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण विकास सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों एवं प्रखंड-अंचल कार्यालयों को सहयोग शिविर से संबंधित प्राप्त आवेदनों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से 30 जून 2026 को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के लिए प्राप्त परिवाद पत्रों के समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया गया। उन्होंने आरटीपीएस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया। समीक्षा के क्रम में जिलांतर्गत बाढ़ प्रभावित अंचलों—नवहट्टा, सलखुआ, महिषी एवं सिमरी बख्तियारपुर—में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भीषण गर्मी एवं लू की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक एहतियाती उपायों की भी समीक्षा की गई।

## कोलकाता में माई भारत के तहत सात दिवसीय 'वंदे मातरम् कैंप' का शुभारंभ

लोकतंत्र की शानः मोहम्मद शबीब आलम

**कोलकाताः** राष्ट्रऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की विरासत और राष्ट्रीय एकता के उत्सव को समर्पित कार्यक्रम में देशभर से आए युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माई भारत (MY Bharat) पश्चिम बंगाल द्वारा ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित सात दिवसीय आवासीय 'वंदे मातरम् कैंप' का शुभारंभ 24 जून 2026 को कोलकाता स्थित विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। "वंदे मातरम् : ए ट्रिब्यूट टू द सॉन्ग दैट अवेकन्ड द नेशन" विषय पर आयोजित यह कैंप राष्ट्रऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को समर्पित है, जिनकी महान रचनात्मक चेतना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिनिधि इस सप्ताहभर चलने वाले आवासीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन तथा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) शंकर गंगोपाध्याय, माई भारत पश्चिम बंगाल के राज्य निदेशक श्री देब कुमार चट्टोपाध्याय तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर (डॉ.) गंगोपाध्याय ने 'वंदे मातरम्' के ऐतिहासिक महत्व तथा देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को गहराई से समझने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

## सड़क सुरक्षा अभियान में बड़ी कार्रवाई, 58 वाहनों से 2.26 लाख जुर्माना वसूला गया

लोकतंत्र की शानः मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता

**सहरसाः** सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327E एवं 107 पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत बरनवाल के नेतृत्व में पंचगछिया, बिहरा थाना एवं बैजनाथपुर क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों के खिलाफ समन एवं चालान जारी किए गए। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी), बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। इसके अतिरिक्त ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर तथा अन्य व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों की भी सघन जांच की गई। जांच के क्रम में कई ऐसे वाहन चालक पाए गए जो हेलमेट पहनने के बजाय वाहन में टांगकर चल रहे थे। ऐसे चालकों को रोककर हेलमेट पहनाया गया तथा भविष्य में अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अंतिम चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सीट बेल्ट एवं हेलमेट का नियमित उपयोग करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। अभियान के दौरान बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायियों को भी निर्देश दिया गया कि वे अपनी दुकानों के सामने ट्रक, ट्रैक्टर एवं अन्य भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा न करें, ताकि यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। विशेष जांच अभियान में मोटर वाहन निरीक्षक बृजमोहन पटवारी, प्रवर्तन अवर निरीक्षक रुपेश, पल्लवी मेहराब, आनंद सहित परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल, चालक, सिपाही एवं गृहरक्षक बल के जवान सक्रिय रूप से शामिल रहे। अभियान के दौरान 40 मोटरसाइकिल, 5 ऑटो रिक्शा, 8 ई-रिक्शा, 5 ट्रैक्टर सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 58 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

## दूध देने निकले अधेड़ का शव गड्ढे में मिला, गला घोंटकर हत्या की आशंका

लोकतंत्र की शानः पटना

- पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतेजार

पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र के बरुआने गांव के पास गड्ढे में एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान नालंदा जिले के सरमेरा थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव निवासी भूषण सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

**घर वापस नहीं लौटने पर शुरू हुई खोजबीनः** जानकारी के अनुसार, भूषण सिंह हर दिन की तरह बीते शाम दूध देने के लिए पटना के बरुआने गांव गए थे। जब देर रात तक वह अपने घर वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को किसी अनहोनी की चिंता सताने लगी। उनके बेटे, जो दिल्ली जा रहे थे, ने रास्ते से ही गांव के कुछ युवकों को फोन कर अपने पिता की खोजबीन करने के लिए भेजा। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने बरुआने खंदा में भूषण सिंह का शव पड़ा हुआ देखा।

परिजनों के मुताबिक, शव के गले में एक गमछा कसकर लपेटा हुआ था, जिससे फंदा लगाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अपराधियों ने भूषण सिंह की न सिर्फ गला घोंटकर, बल्कि गोली मारकर भी हत्या की है। हालांकि, हत्या की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजन भी किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी के कारण को स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं।

## मोहर्रम को लेकर बिहटा में पटना पुलिस का फ्लैग मार्च

लोकतंत्र की शानः पटना

पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में मोहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह पुलिस टीम ने इलाके में बाइक से फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी शामिल रहा। इसका उद्देश्य पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया।

**जुलूस वाले इलाकों में बढ़ाई गई चौकसीः** बिहटा क्षेत्र में मोहर्रम के दौरान कई स्थानों से जुलूस निकाले जाते हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी की तैयारी की है। पुलिस ने साफ किया है कि अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या हुड़दंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

**डीजे पर रोक, ड्रोन से होगी निगरानीः** अमित कुमार ने बताया कि मोहर्रम को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तहत गुरुवार से पूरे क्षेत्र में बाइक फ्लैग मार्च शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जहां आवश्यकता होगी, वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जुलूस के दौरान डीजे के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे आयोजन पर नजर रखी जाएगी।

## मंडन भारती कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग, मत्स्यगंधा मंदिर समिति के पुनर्गठन को लेकर विधायक ने लिखा पत्र

लोकतंत्र की शानः मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता

**सहरसाः** इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सहरसा सदर विधायक ई. आईपी गुप्ता ने जिले के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार पहल जारी रखी है। इसी क्रम में उन्होंने बिहार विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में सहरसा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रस्तावों को उठाया, वहीं मत्स्यगंधा स्थित रक्तकाली चौसठ योगिनी धाम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर जिला पदाधिकारी को पत्र भी प्रेषित किया है। विधायक ने बताया कि पटना में आयोजित याचिका समिति की बैठक में परिवहन, कृषि, शिक्षा, खेल तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सहरसा के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने सहरसा को पूर्णिया से अलग स्वतंत्र परिवहन प्रमंडल बनाने, आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की मांग की। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने सहरसा बस्ती स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत उन्नत करने तथा जेईई मेन्स सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र सहरसा में स्थापित करने की मांग उठाई। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सहरसा को बाजार समिति निर्माण योजना में शामिल करने तथा मंडन भारती कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की। साथ ही ग्रामीण हाटों के विकास पर भी जोर दिया। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहरसा के लिए राशि आवंटन, बुडको एवं नगर निगम में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति तथा वेंडिंग जोन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की मांग रखी। खेल विभाग की समीक्षा के दौरान प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

## संक्षिप्त समाचार

### आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर गूंजा लोकतंत्र का संकल्प, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने याद दिलाया काला अध्याय

**(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी।** भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में संविधान हत्या दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आपातकाल के दौर को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) का सम्मान किया गया और उनके योगदान को स्मरण किया गया। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है, जब देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र सेनानियों का त्याग एवं बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

### मेड़ता रोड के प्राचीन जबरेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते को लेकर न्यायालय का सार्वजनिक समन जारी

**3 जुलाई को होगी सुनवाई**

**लोकतंत्र की शान : मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी।** मेड़ता के सिविल न्यायालय ने मेड़ता रोड स्थित प्राचीन श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर के कथित पारंपरिक रास्ते (सुखाधिकार) को लेकर दायर वाद में आम जनता को पक्षकार बनने का अवसर देते हुए सार्वजनिक समन जारी किया है। न्यायालय ने आदेश-1 नियम-8 सीपीसी के तहत यह समन जारी करते हुए 3 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी समन के अनुसार, वादी श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर बोर्ड ट्रस्ट, मेड़ता रोड की ओर से ट्रस्टीगण सोहनलाल ओझा एवं पूर्णमचंद टाक ने उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक तथा जोधपुर मंडल के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सिविल वाद दायर किया है। वाद में कहा गया है कि मेड़ता रोड स्थित प्राचीन श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव-पार्वती की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं तथा मंदिर के उत्तरी दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार (पोल) और उससे जुड़े आठ दुकानों के सामने का निकास मार्ग लंबे समय से मंदिर ट्रस्ट, श्रद्धालुओं और आमजन द्वारा निर्बाध रूप से उपयोग में लिया जाता रहा है। इसी मार्ग के माध्यम से दुकानों तक आवागमन भी होता है, जिनसे प्राप्त किराये से मंदिर ट्रस्ट को आय होती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेलवे विभाग ने बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाए तथा बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिए 18 जून 2026 को मंदिर के मुख्य द्वार और दुकानों के सामने स्थित निकास मार्ग के बिल्कुल समीप लगभग चार फीट चौड़ी नींव खोदकर रास्ते को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवाद का संबंध केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं होकर आम जनता के हित से भी जुड़ा है, आदेश-1 नियम-8 सीपीसी के तहत सार्वजनिक समन जारी किया है।

### सोनीपतः खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बढ़ी प्रतिस्पर्धा, 930 आवेदन

**लोकतंत्र की शान : सोनीपत।** हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण के संदर्भ में कुलपति अशोक कुमार ने गुरुवार को बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। विश्वविद्यालय के 30 शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अब तक लगभग 930 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 28 कार्यक्रमों के लिए 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे, जिनके लिए लगभग 1100 आवेदन मिले थे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय में नए और पुराने विद्यार्थियों सहित लगभग 750 विद्यार्थी नामांकित थे। इसी आधार पर हरियाणा खेल विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में देश का तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना था। कुलपति के अनुसार इस वर्ष प्राप्त आवेदनों में लगभग 28 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के हैं। वहीं लगभग 70 प्रतिशत आवेदन हरियाणा के अभ्यर्थियों से मिले हैं, जबकि शेष आवेदन अन्य राज्यों से प्राप्त हुए हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में बीपीईएस तथा बीएससी स्पोर्ट्स साइंस के प्रति विद्यार्थियों का विशेष रुझान देखने को मिल रहा है। इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अब तक लगभग 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एथलेटिक्स डिप्लोमा को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है और इसमें आवेदनों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स के लिए जंपिंग, रनिंग और थ्रोइंग स्पर्धाओं के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की उपलब्धता अभ्यर्थियों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों से भी युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ी है। बॉक्सिंग, कबड्डी, शूटिंग, हॉकी, बास्केटबॉल और कुश्ती पाठ्यक्रमों में भी इस वर्ष अच्छा उत्साह है। विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर आठ जुलाई कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 14 जुलाई को बीपीईएस की प्रवेश परीक्षा होगी। 15 जुलाई को एमपीईएस, एमएससी और बीएससी की शारीरिक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 16 और 17 जुलाई को पीजी डिप्लोमा कोचिंग पाठ्यक्रमों तथा 18 जुलाई को पीजी डिप्लोमा स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा होगी।

# शहरी सेवा शिविर में जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर

**» प्रभारी आनंद सिंह चांदावत ने किया निरीक्षण**

लोकतंत्र की शान

**मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी।** राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से 15 जुलाई तक चल रहे शहरी सेवा शिविर के तहत बुधवार को मेड़ता रोड में आयोजित शिविर का नव नियुक्त शिविर प्रभारी आनंद सिंह चांदावत ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चांदावत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी लंबित समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ें। शिविर में शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग की ओर से हरिओम शर्मा तथा जलदाय विभाग की ओर से जगदीश विश्नोई सहित अन्य अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी देते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया।

## एक क्लिक की गलती पड़ सकती है भारी, 'सेफ क्लिक 2.0' से सीधी पुलिस ने दी साइबर सुरक्षा की सीख

**(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान**

**सीधी।** पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित "सेफ क्लिक 2.0" अभियान के तहत जिलेभर में साइबर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। पुलिस अधीक्षक सीधी श्री संतोष कोरी के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलों, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम थाना जमोड़ी अंतर्गत क्राइस्ट ज्योति स्कूल में हुआ, जहां एसपी श्री संतोष कोरी ने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, पहचान चोरी और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही सभी को साइबर सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। मड़वास, खड्डी, भुईमाड़, कुसमी, अमिलिया और मझौली क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में भी विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं कोतवाली, अजाक, बहरी और चुरहट क्षेत्र में आमजन को साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया।

## नशे के खिलाफ जिला न्यायालय से बुलंद हुई आवाज, नशामुक्त समाज बनाने का लिया संकल्प

**(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान**

**सीधी।** अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में जनजागरूकता एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय तक समान पहुंच दिलाना विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

## केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद ने सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ पर जताई चिंता

**लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश**

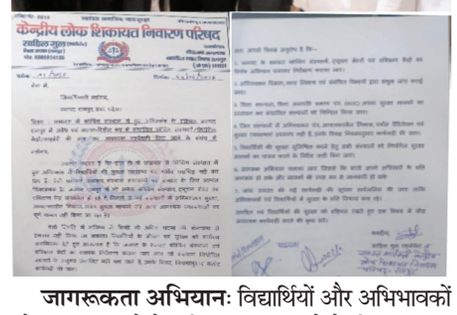


**रामपुर** – परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई संस्थान ऐसे हैं जहां अग्निशमन सुरक्षा, आपातकालीन निकास और वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। वकीलों ने चिंता जताई कि बिना मान्यता और मानकविहीन तरीके से चल रहे ये संस्थान किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

**ज्ञापन में की गई ये प्रमुख मांगें:** अधिवक्ता साहिल गुल ने जिला प्रशासन से निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है:

**संयुक्त जांच अभियान:** अग्निशमन विभाग, नगर निकाय और शिक्षा विभाग की एक संयुक्त टीम बनाकर सभी संस्थानों का गहन निरीक्षण किया जाए।

**मानकों की जांच:** बिना NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।

**सुरक्षा व्यवस्था:** प्रत्येक संस्थान में अग्निशमन यंत्रों और सुरक्षित आपातकालीन निकास की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

**जागरूकता अभियान:** विद्यार्थियों और अभिभावकों को सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।

**सार्वजनिक सूचना:** जांच के बाद की गई कार्यवाही का विवरण सार्वजनिक किया जाए ताकि अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बना रहे।

## मेड़ता रोड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

**» घरों और गलियों में भरा पानी**
**» सुबह 5 बजे शुरू हुई बारिश 11 बजे तक जारी,**
**» कई कॉलोनियों में जलभराव से लोगों को हुई भारी परेशानी**

लोकतंत्र की शान

**मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी।** मेड़ता रोड कस्बे में गुरुवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई तेज बारिश लगातार लगभग 11 बजे तक जारी रही। छह घंटे तक हुई लगातार वर्षा के कारण कस्बे के अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और परिवारों को घरों से पानी बाहर निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बारिश के बाद सबसे अधिक समस्या बाईपुरा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां बरसाती पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण गलियों और मोहल्लों में पानी भर गया। जल निकासी व्यवस्था की पोल खुलने से लोगों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में हर वर्ष यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया है। कस्बे के महादेव नगर में बारिश के दौरान बिजली के तार गिर जाने से एहतियात के तौर पर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। इससे क्षेत्र के लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। वहीं संबंधित विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बिजली व्यवस्था को सुरक्षित रूप से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की। बारिश का असर नागौर रोड, सदर बाजार सहित विभिन्न कॉलोनियों में भी देखने को मिला, जहां सड़कों और गलियों में पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित रहा। कई स्थानों पर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बाजार क्षेत्र में भी जलभराव के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। लगातार हुई बारिश ने मेड़ता रोड में अधूरे विकास कार्यों और कमजोर जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर भी सामने ला दी। जहां-जहां नालों का निर्माण अधूरा है या सफाई समय पर नहीं हुई, वहां पानी लंबे समय तक जमा रहा। लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बरसात के दौरान आमजन को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

## सोन नदी में समाए दो युवक, बारात की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

**(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान**

**सीधी।** जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत सिहावल चौकी क्षेत्र के ग्राम गेरूआ-कितकिन में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। सोन नदी में नहाने गए दो युवक गहरे पानी में डूब गए, जिनका देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार बहरी थाना क्षेत्र के पोखरा गांव से 24 जून को रावत परिवार के यहां बारात आई थी। बारात में शामिल होने आए अवधेश साकेत (18) और संजय साकेत (20) गुरुवार सुबह अपने एक साथी के साथ सोन नदी नहाने पहुंचे। नहाने के दौरान दोनों युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जबकि उनका तीसरा साथी किसी तरह बाहर निकलकर परिजनों को सूचना देने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन देर शाम तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों ने बताया कि दोनों युवक दो दिन पहले ही परदेश से कमाकर घर लौटे थे। शादी की खुशियों के बीच हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है।

## मोहर्रम पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर महापौर श्रीमती सूरी ने किया स्थलीय निरीक्षण

**» श्रद्धालुओं की सुविधा एवं समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश**

**लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश रशीद**

**कटनी गतः** आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती प्रीति सूरी ने मंगलवार सायंकाल मेयर इन काउंसिल सदस्यों एवं निगम अधिकारियों के साथ मदन मोहन चौबे वार्ड एवं गाटर घाट स्थित कर्बला शरीफ पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। महापौर श्रीमती सूरी ने कहा कि मोहर्रम पर्व नगर की सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विशेष साफ-सफाई अभियान,पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, सुगम आवागमन,निर्बाध विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका त्वरित निराकरण किया जाए, ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके।उन्होंने अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी सहयोग एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, जिससे मोहर्रम पर्व पूरी श्रद्धा, आस्था, भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

## नगर पालिका मेड़ता रोड को मिली 9 नए स्थायी पदों की सौगात

**» आउटसोर्सिंग से होंगे सफाई व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य**

लोकतंत्र की शान

**मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी।** राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 328 सहपठित धारा 337 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बजट घोषणाओं के तहत गठित 76 नवीन नगर पालिकाओं के लिए नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत नगर पालिका मेड़ता रोड को भी कुल 9 नए स्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवगठित 76 नगर पालिकाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों के कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराए जाएंगे। इन कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई अलग अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। संबंधित नगर निकाय अपनी वित्तीय क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध संसाधनों से इन कर्मचारियों को नियोजित करेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां एवं पदों को भरने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों, प्रक्रिया एवं आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप ही की जाएगी। सरकारी आदेश के अनुसार नवगठित 76 नगर पालिकाओं के लिए कुल 684 नए पदों के सृजन को वित्त (व्यय-3) विभाग की आईडी क्रमांक 172601115 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में गठित छह नगर पालिकाओं—गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं), रानीवाड़ा (जालौर), जावाल (सिरोही), लालगढ़-जाटान (श्रीगंगानगर), ऋषभदेव (उदयपुर) तथा सेमारी (उदयपुर)—के लिए पूर्व में स्वीकृत कुल 54 पदों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इन नगर पालिकाओं के पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित हो जाने के कारण वित्त विभाग के निर्देशानुसार इनके सभी स्वीकृत पद निरस्त कर दिए गए हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत फिर शुरु करेगा पर्यटक वीजा की सुविधा

**ढाका।** बांग्लादेश में नव नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने घोषणा की है कि भारत लगभग दो साल के अंतराल के बाद 28 जून से बांग्लादेश के लोगों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने यहां बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को गुरुवार को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया और जमुना फ्यूचर पार्क स्थित भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) का दौरा कर चल रही वीज़ा प्रक्रियाओं की समीक्षा की। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जमुना फ्यूचर पार्क स्थित आईवीएसी भारत के सबसे बड़े वीज़ा सहायता केंद्रों में से एक है और भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने जानकारी दी कि रविवार से बांग्लादेश के लोगों के लिए पर्यटक वीजा की सुविधा फिर शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हुईं अप्रिय घटनाओं के बीच बांग्लादेश के लोगों के लिए पर्यटन वीजा की सुविधा स्थगित कर दी गई थी। इस बीच बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किये गये दिनेश त्रिवेदी को सरकारी समारोहों के लिए केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर प्रोटोकॉल दिया गया है। सरकार ने औपचारिक कार्यक्रमों के लिए उन्हें मंत्री का प्रोटोकॉल दिए जाने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के लोकाचार विभाग की ओर से बुधवार को जारी एक शासनादेश में कहा गया है कि त्रिवेदी को 'टेबल ऑफ़ प्रेसिडेंस' में यह बराबर का दर्जा व्यक्तिगत तौर पर दिया गया है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि यह पद सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों के लिए है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता त्रिवेदी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उच्चायुक्त का पद मंत्री के नीचे आता है। इसलिए विदेश मंत्री के दौरे में समारोहों में बैठने के प्रोटोकॉल में उनके राजनीतिक कद के हिसाब में कोई असहजता नहीं हो, इसलिए यह निर्णय जरूरी था। श्री त्रिवेदी बंगाली भाषा में माहिर हैं। उन्हें 27 अप्रैल को बांग्लादेश में भारत का दूत नियुक्त किया गया था। हाल के वर्षों में किसी राजनेता की यह पहली राजनयिक नियुक्ति की गई है।

### भूकंप के बाद वेनेजुएला ने इमरजेंसी घोषित की

**मॉस्को।** वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश के इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बुधवार रात को, अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो ज़बरदस्त भूकंप आए। ये भूकंप मोरोन शहर से 16 किलोमीटर (9.9 मील) और सैन फेलिप से 24 किलोमीटर दूर आए। रोड्रिगेज ने बुधवार रात एक वीडियो संदेश में कहा, "हम अपने संविधान के प्रावधानों के अनुसार आपातकाल घोषित कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भारी नुकसान के कारण वेनेजुएला का मुख्य हवाई अड्डा, माइक्वेटिया, बंद कर दिया गया है। रोड्रिगेज ने बताया, "कुछ राज्य ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राजधानी काराकस में कई इलाकों में इमारतें ढह गई हैं। मिरांडा और ला गुएरा राज्यों को भी भारी नुकसान हुआ है... साथ ही अरागुआ, काराबोबो और फाल्कन राज्यों को भी नुकसान पहुंचा है।" उन्होंने बताया कि दो भूकंपों के बाद अब तक 20 भूकंप के बाद के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। रोड्रिगेज ने कहा, "मैं दुनिया भर की उन सरकारों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने भूकंप के तुरंत बाद एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए वेनेजुएला से संपर्क किया।" उनके अनुसार, अमेरिका, पनामा, कतर, क्यूबा, निकारागुआ, तुर्की, जॉर्डन, कोलंबिया, बारबाडोस, ब्रिटेन, ब्राजील और मैक्सिको ने तुरंत वेनेजुएला के प्रति अपना समर्थन जताया। खबरों के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी वेनेजुएला सरकार से संपर्क किया और प्राकृतिक आपदा के नतीजों से निपटने में मदद करने की अपनी इच्छा जताई।

### सौनी स्कूल के आकस्मिक निरीक्षण में बच्चों से संवाद, पढ़ाई और अनुशासन पर दिया जोर

**बलरामपुर।** जिले के ग्राम सौनी स्थित माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक छात्रा की प्रतिभा ने कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी का दिल जीत लिया। कक्षा सातवीं की छात्रा सोनी पाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 18 का पहाड़ा सुनाया, जिससे प्रभावित होकर कलेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाकर सराहना की और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कलेक्टर ने गुरुवार को विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति तथा शिक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से आत्मीय संवाद किया और हिंदी, गणित तथा सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछकर उनकी शैक्षणिक समझ का आकलन किया। विद्यार्थियों को बिना झिझक उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने नियमित अध्ययन और अभ्यास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में निरंतरता और मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हाई स्कूल के निरीक्षण के दौरान भी उन्होंने विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और उन्हें प्रतिदिन लेखन अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नियमित लिखने से सीखने की क्षमता बढ़ती है और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। संवाद के दौरान जब कलेक्टर ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा तो बच्चों ने डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी और अन्य क्षेत्रों में जाने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए अनुशासन, लगन और निरंतर मेहनत आवश्यक है। कलेक्टर ने शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित विद्यालय आने से बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहती है और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही शिक्षकों को अभिभावकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और अनुपस्थित विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय लाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने सीजीवीएसके ऐप के माध्यम से शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

### लूट का विरोध करने पर फैक्टरी कर्मी की चाकू मारकर हत्या, तीन नाबालिग दबोचे

**नई दिल्ली।** रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में लूटपाट के दौरान 60 वर्षीय फैक्ट्री कर्मी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन नाबालिगों को पकड़ लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दो चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 23 जून को बेगमपुर थाने में पीसीआर कॉल मिली थी कि पंसाली रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया जा चुका था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी राजेश के रूप में हुई। वह प्रताप विहार स्थित एक फैक्टरी में मजदूरी करता था। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान बेगमपुर थाना और रोहिणी स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीमों ने मृतक की गतिविधियों का पता लगाया और उसके कार्यस्थल से लेकर घटनास्थल तक की पूरी कड़ी खंगाली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और तकनीकी निगरानी के जरिए संदिग्धों की पहचान की। जांच में तीन नाबालिगों की भूमिका सामने आई, जिनकी गतिविधियां वारदात के समय घटनास्थल के आसपास पाई गईं। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपराध में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पुलिस जांच में पता चला कि तीनों नाबालिग लूटपाट की नीयत से घटनास्थल के आसपास घूम रहे थे। इसी दौरान उन्होंने साइकिल से जा रहे राजेश को रोक लिया। एक आरोपित ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया, जबकि बाकी दो ने उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर मुख्य आरोपित ने राजेश पर चाकू से हमला कर दिया।

# मप्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ट्रक में घुसी बेकाबू कार, 4 की मौत

**एजेंसी, मंदसौर**

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर सीतामऊ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले छह लोग रेनॉल्ट ट्राइबर कार में सवार होकर किसी काम से दिल्ली जा रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वे सीतामऊ थाना क्षेत्र में ग्राम तितरोद के पास पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बेहद तेज रफ्तार में थी और वह अनियंत्रित होकर अचानक सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकालकर सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर कर दिया।

सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापत ने बताया कि मृतकों की पहचान सचिन गंगाधर पुत्र अजय पांडुरंग निवासी समोर (औरंगाबाद), संदीप पुत्र नवनाथ रामराव बोरसे निवासी छत्रपति नगर सावंगी (औरंगाबाद), राजेंद्र कोवडे पुत्र भावराम कोवडे उम्र निवासी संभाजी नगर (औरंगाबाद) और रवींद्र काले पुत्र भागवत काले निवासी शास्त्री नगर संभाजी नगर (औरंगाबाद) के रूप में हुई है। वहीं, अब्दुल खलील (30) पुत्र अब्दुल समद निवासी औरंगाबाद और उमर (32) पुत्र इस्माइल जागीरदार निवासी गंगापुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक परिजनों को सूचना दे दी गई है। संभवतः वे गुरुवार देर रात या शुक्रवार सुबह तक मंदसौर पहुंचेंगे, जिसके बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। चारों शवों को सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही रखा गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और एक्सप्रेस-वे के निगरानी सिस्टम की मदद से ट्रक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे का कारण माना जा रहा है।

## एनएचएआई ने घरौंडा टोल प्लाजा पर शुरू की बिना लेन वाली निर्बाध टोल प्रणाली

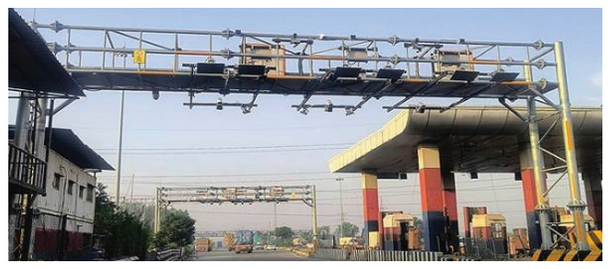

**एजेंसी, नई दिल्ली**

- प्राधिकरण ने एनएच-44 पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 44 के पानीपत–जालंधर खंड पर घरौंडा टोल प्लाजा में बहु लेन निर्बाध परिवहन (एमएलएफएफ) यानी बिना 'अवरोधक' वाली और प्रौद्योगिकी आधारित टोल प्रणाली शुरू की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम को शुरू कर दिया है। घरौंडा यह हरियाणा का पहला बैरियर-रहित टोल सिस्टम है, जहां वाहन बिना रुके और गति कम किए बिना गुजर सकते हैं और फास्टैग के जरिए अपने आप टोल कट जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस नई तकनीक की मदद से वाहनों को टोल चुकाने के लिए रुकने या धीमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। एनएचएआई ने इससे पहले गुजरात के चोर्यासी, दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा और राजस्थान के दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। इसी कड़ी में घरौंदा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग का कार्यान्वयन भारत के आधुनिक, कुशल और सुगम राजमार्ग नेटवर्क की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

## तकनीकी कार्य के कारण साबरमती और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित

**एजेंसी, जोधपुर**

जम्मू मंडल के मुकेरियां-तलवाड़ा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते जम्मूतवी-साबरमती-जम्मूतवी एवं शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन आगामी दिनों में प्रभावित रहेगा। इसके तहत जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा,जबकि शालीमार एक्सप्रेस का मुकेरियां स्टेशन पर अस्थाई रूप से ठहराव निरस्त रहेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार तकनीकी कार्य के कारण जम्मूतवी-साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस छह दिनों तक जालंधर सिटी -ब्यास-तरनतारन-अमृतसर-गुरदासपुर मार्ग से संचालित होगी। वहीं शालीमार एक्सप्रेस मुकेरियां स्टेशन पर पांच दिनों तक नहीं रुकेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 19224,जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस एक जुलाई तक जम्मूतवी से प्रस्थान के दौरान गुरदासपुर-अमृतसर-तरनतारन-ब्यास-जालंधर सिटी के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन पठानकोट कैंट,मीरथल, मुकेरियां,दसुआ,टांडा उड़मुड़ एवं भोगपुर सिरवाल स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। इसी प्रकार वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 19223,साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 30 जून तक साबरमती से प्रस्थान के दौरान ब्यास-तरनतारन-अमृतसर-गुरदासपुर मार्ग से संचालित होगी।

## कोलकाता हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई नौ, घायलों और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि का ऐलान

**एजेंसी, कोलकाता**

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदाम ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अब तक मलबे से 29 लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, घायलों को एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु के अनुसार, उपचाराधीन 20 लोगों में 15 की स्थिति स्थिर है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना के जवान लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। बचाव दलों ने आशंका जताई है कि मलबे में अभी कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन घायलों की स्थिति बातचीत करने लायक थी, उनसे हादसे के संबंध में जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि मृतकों के जीवन की भरपाई किसी आर्थिक सहायता से नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहयोग देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृत श्रमिकों के परिजनों के लिए दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने हादसे को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कोलकाता को असुरक्षित बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने गार्डनरीच हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना को नहीं बुलाया गया था तथा भारी लोहे के बीम काटने के लिए पर्याप्त आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध नहीं थीं। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दावा किया कि तारातला गोदाम के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों में नगर निगम के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति काली का भी नाम लिया, जिसे उन्होंने नगर निगम के पूर्व मेयर का निजी सहायक बताया।

## खुटपाली डायवर्सन परियोजना का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, किसानों को मिलेगी बेहतर सिंचाई सुविधा

**एजेंसी, बलरामपुर**

- नई पाइपलाइन तकनीक से पानी का होगा निर्बाध प्रवाह, परियोजना पूरी होने पर कई गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

जिले की महत्वपूर्ण खुटपाली डायवर्सन परियोजना का गुरुवार को कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों और तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने परियोजना स्थल का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से जल संग्रहण, पाइपलाइन निर्माण, जल परिवहन प्रणाली तथा किसानों तक पानी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खुटपाली डायवर्सन परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। परियोजना के तहत लगभग 1.4 मीटर व्यास की बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके माध्यम से पानी का सुरक्षित और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी। अब नई तकनीक के साथ परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं की संभावना काफी कम हो जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को सिंचाई के साथ-साथ जल उपलब्धता के क्षेत्र में भी बड़ा लाभ मिलेगा। परियोजना के माध्यम से रामानुजगंज क्षेत्र तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा। सिंचाई का रकबा बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। विशेष रूप से रबी सीजन में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इस परियोजना से कोटपाली, बसकेपी, खुजरी, चिरकोमा और महराजगंज सहित आसपास के गांवों के किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को परियोजना के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता बनाए रखने और कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचना चाहिए और कार्य समय-सीमा में पूर्ण होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. मिंज, एसडीओ, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

## एनसीबी ने निकाली ड्रग विरोधी रैली, नशा मुक्ति का लिया संकल्प

**एजेंसी, जोधपुर**

नशा मुक्त भारत पखवाड़ा और अंतरराष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोधपुर जोनल यूनिट द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से ड्रग-विरोधी रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने किया। रैली का शुभारंभ सुबह पावटा सर्किल से हुआ, जिसे बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान के आईजी एमएल गर्ग, जोधपुर रेंज के आईजी सत्येंद्र सिंह, एनसीबी जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी, पीटीएस के डिप्टी आईजी देवेंद्र विश्नोई तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर पंकज खत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिंदगी को हां, नशे को ना थीम पर आयोजित यह वॉकाथॉन शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उम्मेद स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से नशा विरोधी शपथ ली। कार्यक्रम में बीएसएफ, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, राजस्थान पुलिस, एनसीसी, स्काउट-गाइड, शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ, समाजसेवी संगठनों सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए घनश्याम सोनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता, रोकथाम और जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने युवाओं से नशा विरोधी अभियान के दूत बनने का आह्वान किया तथा समाज के सभी वर्गों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

## शैक्षिक संचार संघ की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित

**एजेंसी, जोधपुर**

डिजिटल शिक्षा, मूक्स तथा उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सहभागिता के बढ़ते महत्व को देखते हुए शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) ने वर्ष 2026 के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सीईसी तथा उसकी विभिन्न पहलों के प्रति जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

इस पहल से सीईसी के मूक पाठ्यक्रमों एवं अन्य डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों के व्यापक प्रसार, अधिकाधिक सहभागिता एवं नामांकन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ संस्थागत सहयोग और शैक्षणिक सहभागिता को भी बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

अपने आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत सीईसी की ओर से ईएमआरसी जोधपुर के सहयोग से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए मूक्स जागरूकता विषयक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ईएमआरसी जोधपुर के निदेशक प्रो. महिपाल सिंह राठौड़ ने आगामी वर्ष के जनवरी सत्र से शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) के मूक्स पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने में गहरी रुचि एवं उत्साह व्यक्त किया। कार्यशाला का औपचारिक समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

गौरतलब है कि शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों में से एक है। इसकी स्थापना उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। अपने 20 मीडिया केंद्रों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से सीईसी स्वयमं, मूक पाठ्यक्रमों के व्यवस्थित विकास तथा डीटीएच चैनलों पर प्रसारण हेतु शैक्षणिक सामग्री के निर्माण में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिससे उच्च शिक्षा तक व्यापक एवं समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

## नितिन नवीन बोले– 25 जून 1975 को लोकतंत्र पर हुआ सबसे बड़ा आघात

**एजेंसी, नई दिल्ली**

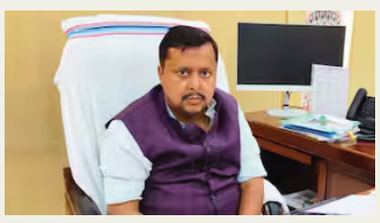

देशभर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुरुवार को संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़े प्रभाव को याद किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार की राजधानी पटना में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में संगोष्ठियां, प्रदर्शनी और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपातकाल को याद करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को भारतीय लोकतंत्र पर स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आघात किया गया। सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपा गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने का प्रयास हुआ। एक्स पर साझा किए अपने संदेश में नितिन नवीन ने कहा कि यह दिन हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और स्वतंत्रता की महत्ता का स्मरण कराता है। उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। दशकों तक आपातकाल के इस काले अध्याय को देश की सामूहिक स्मृति से मिटाने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और संविधान पर हुए इस प्रहार को इतिहास के हाशिये पर धकेल दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लेकर इतिहास के साथ न्याय किया गया। संविधान हत्या दिवस हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह संकल्प भी कराता है कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सभी को सदैव सजग और समर्पित रहना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो दल आज संविधान की दुहाई देता है, उसने आज तक आपातकाल के लिए देश से बिना शर्त माफी क्यों नहीं मांगी? यदि सचमुच संविधान की चिंता होती, तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या के उस अपराध के लिए देश से क्षमा मांगी जाती।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद राष्ट्रहित नहीं, बल्कि सत्ता हित को प्राथमिकता दी गई। एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। भारत सरकार ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

# भारत में अवैध गौण खनिज उत्खनन मिलीभगत? -खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 में त्वरित संशोधन की आवश्यकता- विकास, पर्यावरण और अगली पीढ़ियों के भविष्य पर मंडराता संकट -समग्र व्यापक विश्लेषण



एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» भारत को खनिज संपन्न राष्ट्र से आगे बढ़कर खनिज संरक्षण और सतत विकास का वैश्विक मॉडल बनने की दिशा में ठोस कदम उठाने की त्वरित आवश्यकता

» खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय प्रभावशाली तत्वों, खनन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ़ विशेष कठोर प्रावधान की आवश्यकता -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक रहा है। रेत, मुरुम, गिट्टी, पत्थर, मिट्टी और अन्य गौण खनिजों ने न केवल देश के निर्माण क्षेत्र को गति दी है बल्कि ग्रामीण और शहरी विकास की आधारशिला भी रखी है।किंतु पिछले कुछ दशकों में जिस तीव्र गति से इन संसाधनों का दोहन हुआ है, उसने एक गंभीर राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया है। यह संकट केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय विनाश, प्रशासनिक भ्रष्टाचार व राजनीतिक संरक्षण का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण राजस्व हानि और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र आम नागरिकों को बताना चाहूंगा क्रि भारत में खनन गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 (एमएमडीआर एक्ट) के तहत होता है।मेरा सुझाव है कि इसमें प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय प्रभावशाली तत्वों,खनन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ़ विशेष कठोर प्रावधान के उल्लेख की आवश्यकता है,क्योंकि अवैध खनन प्राय इन्हीं लोगों के इशारों या सलंग्नता में होता है यानें शासन प्रशासन व इस वर्ग के साथ यह खेला सुचारू रूप से चलता है। यह प्राय सभी लोगों को मालूम है लेकिन सभ मूक रहते हैं। बता दूं क्रि इस कानून के अनुसार गौण खनिजों के नियमन और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। राज्यों को अधिकार दिए गए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाएं,पट्टे जारी करें, रॉयल्टी निर्धारित करें तथा अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करें।सिद्धांत रूप से यह व्यवस्था अत्यंत प्रभावी दिखाई देती है,किंतु व्यवहार में अनेक राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। कानून मजबूत हैं,नियम पर्याप्त हैं, दिशा निर्देश मौजूद हैं,लेकिन क्रियान्वयन अक्सर कमजोर पड़ जाता है।यही वह स्थान है जहां प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय प्रभावशाली तत्वों,खनन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के आरोप सामने आते हैं।देश के लगभग हर राज्य में समय-समय पर अवैध रेत खनन,नदी घाटों से चोरी, पहाड़ियों की कटाई और वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की खबरें सामने आती रही हैं। कई मामलों में स्थानीय नागरिकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ईमानदार अधिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें दबाव, धमकियों और हिंसा तक का सामना करना पड़ा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक नायब तहसीलदार पर हमला इसी मामले की कड़ी है,यह स्थिति दर्शाती है कि अवैध खनन केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी चुनौती बन चुका है। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार 25 जून 2026 को राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत जानकारी महाराष्ट्र विधानमंडल के पावसाळी अधिवेशन (मानसून सेशन 2026) के चौथे दिन,विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने आधिकारिक घोषणाएं कीं और सीधे विधानसभा से लाइव आकर भी इसकी जानकारी साझा की, राज्य में हो रहे अवैध गौण खनिज उत्खनन को रोकने और अपराधियों पर मकोका/ एमपीडीए जैसी सख्त कार्रवाई के लिए एक स्वतंत्र 'टास्क फोर्स' का गठन कियाजाएगा इसी व्यापक राष्ट्रीय समस्या की ओर संकेत करती है।सरकार ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन और विभागीय जांच की जाएगी। संयुक्त उड़नदस्ते बनाए जाएंगे,ड्रोन तकनीक का उपयोग होगा,अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा तथा जिलाधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। यह नीति और दृष्टिकोण निश्चित रूप से सराहनीय है। किंतु बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन आदेशों का धरातल पर कठोर और निरंतर क्रियान्वयन हो पाएगा ? क्योंकि भारत में समस्या कानूनों की कमी नहीं,बल्कि उनके निष्पक्ष और सटीकता से प्रभावी पालन की है।




साथियों, अवैध खनन का सबसे पहला और सबसे गंभीर प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। जब नदियों से अनियंत्रित मात्रा में रेत निकाली जाती है, तो नदी की प्राकृतिक संरचना बिगड़ जाती है। नदी का तल गहरा होने लगता है, जलधारण क्षमता प्रभावित होती है और आसपास के भूजल स्तर में गिरावट आने लगती है। परिणामस्वरूप कुएं, हैंडपंप और बोरवेल सूखने लगते हैं। कई क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई संकट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कुछ लोगों के अल्पकालिक आर्थिकr लाभ के कारण संपूर्ण क्षेत्र का जल संतुलन बिगड़ जाता है।रेत केवल निर्माण सामग्री नहीं है;यह नदियों केपारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। रेत नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है, तटों को स्थिर रखती है तथा अनेक जलीय जीवों के लिए आवास का कार्य करती है। जब इसका अत्यधिक उत्खनन होता है, तो नदी किनारों का कटाव बढ़ जाता है। कई स्थानों पर पुलों की नींव कमजोर हुई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और नदी तटों पर बसे गांवों को खतरा उत्पन्न हुआ है। यह समस्या केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक प्रभाव डालने वाली बहुत गंभीर समस्या है। साथियों अवैध खनन का दूसरा बड़ा प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। नदी, पहाड़, वन और मिट्टी केवल खनिजों के भंडार नहीं हैं बल्कि हजारों जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का घर हैं। जब बड़े पैमाने पर उत्खनन होता है, तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों के घोंसले,मछलियों के प्रजनन क्षेत्र,वन्यजीवों के आवागमन मार्ग और वनस्पतियों की प्राकृतिक श्रृंखला प्रभावित होती है। पर्यावरण वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कई स्थानीय प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं।भूमि क्षरण भी अवैध खनन की एक गंभीर समस्या है। जब पहाड़ियों और कृषि भूमि के आसपास बिना वैज्ञानिक अध्ययन के खनन किया जाता है, तो मिट्टी की उर्वरता घटती है। भूमि कटाव बढ़ता है और कई बार खेती योग्य क्षेत्र बंजर बन जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कृषि पर आधारित है, धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। इसका सीधा प्रभाव किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार पर पड़ता है। साथियों, अवैध खनन का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर भूमि विनाश, वन कटाई और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण कार्बन अवशोषण की प्राकृतिक क्षमता घटती है। नदियों और जल स्त्रोतों के क्षरण से सूखे और बाढ़ जैसी चरम घटनाओं का खतरा बढ़ता है। आज भारत पहले ही जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अवैध खनन स्थिति को और अधिक जटिल बना सकता है।आर्थिक दृष्टि से भी यह एक राष्ट्रीय नुकसान है।अवैध खनन से सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी और कर राजस्व का बड़ा हिस्सा चोरी हो जाता है।जो धन सार्वजनिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल परियोजनाओं में लगना चाहिए,वह कुछ लोगों की निजी संपत्ति में परिवर्तित हो जाता है।इस प्रकार अवैध खनन केवल पर्यावरण की चोरी नहीं बल्कि जनता केअधिकारों और सरकारी राजस्व की भी चोरी है।अक्सर देखा गया है कि अवैध खनन का नेटवर्क बहुत संगठित होता है। इसमें स्थानीय स्तर से लेकर बड़े आर्थिक हित जुड़े हो सकते हैं। कई बार रात के अंधेरे में नदी घाटों से रेत निकाली जाती है, नकली दस्तावेजों के माध्यम से परिवहन किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है। यदि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक निगरानी कमजोर हो या कुछ अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंद लें, तो अवैध कारोबार फलता-फूलता रहता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी सटीकता से जोर देते हैं। साथियों महाराष्ट्र सरकार द्वारा ड्रोन निगरानी, संयुक्त जांच दल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जिलाधिकारियों को विशेष अधिकार देने जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आधुनिक तकनीक भ्रष्टाचार और मानव हस्तक्षेप को कम कर सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से वास्तविक उत्खनन क्षेत्र की निगरानी संभव है। जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, ई-परमिट प्रणाली और उपग्रह चित्रों का उपयोग अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। किंतु तकनीक तभी सफल होगी जब उसके साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक ईमानदारी भी सटीकता से जुड़ी हो। साथियों, इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अंतरपीढ़ी न्याय अर्थात इंटरजनरेशनल जस्टिस है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं हैं। इन पर आने वाली पीढ़ियों का भी समान अधिकार है। यदि वर्तमान पीढ़ी लालच, भ्रष्टाचार और अल्पकालिक लाभ के कारण प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर देगी, तो भविष्य की पीढ़ियों के पास क्या बचेगा? उन्हें स्वच्छ नदियां,उपजाऊ भूमि,स्थिर पर्यावरण और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए कि यदि अगले 20 से 30 वर्षों तक वर्तमान गति से अवैध खनन चलता रहा तो कई नदियां अपने प्राकृतिक स्वरूप को खो सकती हैं।भूजल संकट और गहरा हो सकता है। निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक खनिजों की कमी पैदा हो सकती है। पर्यावरणीय आपदाएं बढ़ सकती हैं। किसानों, मछुआरों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। यह केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी होगा। साथियों, समाधान केवल सरकार के पास नहीं है। नागरिक समाज, मीडिया, न्यायपालिका, स्थानीय समुदाय और जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रत्येक खनन पट्टे की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। ग्राम सभाओं को निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए। अवैध खनन की सूचना देने वालों को सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर्यावरणीय क्षति का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर दोषियों से वास्तविक क्षतिपूर्ति वसूली जानी चाहिए।साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।वास्तव में अवैध खनन का प्रश्न केवल रेत,मुरुम या पत्थर का प्रश्न नहीं है। यह सुशासन,पर्यावरणीय न्याय,कानून के शासन और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है। यदि कानूनों का कठोरता से पालन हो, तकनीक का प्रभावी उपयोग हो, दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो और राजनीतिक इच्छाशक्ति दृढ़ हो, तो इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन यदि मिलीभगत, भ्रष्टाचार और संरक्षण का चक्र चलता रहा, तो प्राकृतिक संसाधनों की यह लूट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे संकट को जन्म दे सकती है जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगेकि आज आवश्यकता केवल अवैध खनन रोकने की नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रति राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना ही वास्तविक प्रगति है। अन्यथा अल्पकालिक लाभ के लिए किया गया यह अंधाधुंध दोहन भविष्य में जल, भूमि, जैव विविधता और खनिज संसाधनों के ऐसे संकट को जन्म देगा, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। यही समय है जब भारत को खनिज संपन्न राष्ट्र से आगे बढ़कर "खनिज संरक्षण और सतत विकास का वैश्विक मॉडल" बनने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।


**-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318**


# "माँ भारती के चरणों पर समर्पित दो अनमोल हीरे"




बलिदानी अर्धेंदु दस्तीदार और बलिदानी अमरेंद्र नंदी

डॉ.जया शुक्ला

इतिहास का वास्तविक लाभ यह नहीं है कि हम अपनी पुरानी विकसित सभ्यता पर अपनी पीठ ठोकैं, या हमारे देश को विदेशी आक्रान्ताओं के कारण हुई हानि पर आजतक आँसू ही बहाते रहैं और उनकी पीढ़ियौं से भी आजतक नफ़रत ही करते रहैं। इतिहास तो हमैं आगे का सही रास्ता चुन पाने के लिए दृष्टि देने का साधन है। और इसलिये हमैं सच्चे इतिहास को गढ़ी हुई बातौं से छानकर अलग पहचान सकना आना आवश्यक है।

राजनीतिक स्वार्थके कारणौं से स्वार्थी तत्वौं द्वारा, और इतिहास को बेतरह बदलकर, तथाकथित नकली "वीर" प्रचारित किए जा रहे हैं। हमैं उन अनेक गुमनाम महान वीरौं के बारे मैं खोज कर जानकारी हासिल करनी होगी, जिन्होंने परिवार इत्यादि को भूलकर, पूरी निष्ठा के साथ, ग़ुलामी की जंज़ीरौं मैं जकड़े अपने देश को आज़ाद करवाने के लिये सर्वस्व न्योछावर कर दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। यही सच्चा इतिहास हमारी आनेवाली पीढ़ियौं को सही राह दिखायेगा।

स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक अर्धेंदु दस्तीदार और अमरेंद्र नंदी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिनके बारे मैं बहुत कम ज्ञात है। आप प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन (मास्टर-दा) द्वारा संगठित 'इंडियन रिपब्लिकन आर्मी' (चटगांव शाखा) के प्रमुख सदस्य थे। इन दोनों वीर राष्ट्रभक्तों ने 1930 के ऐतिहासिक चटगांव शस्त्रागार छापे (Chittagong Armoury Raid) में सक्रिय भूमिका निभाई थी। शस्त्रागार छापे से पहले, फरवरी 1930 में एक बम विस्फोट में अमरेंद्र नंदी गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसके बावजूद, उन्होंने और अर्धेंदु दस्तीदार ने देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर भाग लिया।

कुछ विशेष क्रान्तिकारी कार्य, जहाँ इनकी भागीदारी थीः—

चटगांव शस्त्रागार छापा:- 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव (अब बांग्लादेश में) में ब्रिटिश पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई गई। अर्धेंदु दस्तीदार इस सशस्त्र विद्रोह का हिस्सा बने।

जलालाबाद पहाड़ी का युद्ध: छापे के बाद क्रांतिकारी जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए। वहाँ 22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना के साथ भयंकर मुठभेड़ हुई।

सर्वोच्च बलिदान: इस छापामार युद्ध और पुलिस मुठभेड़ के दौरान 24 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना की गोलियों का सामना करते हुए इन दोनों युवा देशभक्तों ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। शहादत के समय अर्धेंदु दस्तीदार की उम्र महज 17 वर्ष के आसपास थी।

जया शुक्ला

# वर्दी का भय या कानून का विश्वास?

» गोड्डा की एक घटना, पत्रकार सुरक्षा और झारखंड की कानून-व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल

आलेख – विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला', स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार

लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों, सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि आम नागरिक स्वयं को कितना सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है। जब कोई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भयमुक्त होकर प्रश्न पूछ सकता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में जीवंत माना जाता है। लेकिन जब कानून की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर ही भय पैदा करने के आरोप लगने लगें, तब लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालपुर गाँव में 25 जून 2026 को सामने आई एक कथित घटना ने ऐसे ही अनेक सवालों को जन्म दिया है। आरोप है कि सादे वेश में कुछ पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से गाँव पहुँचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिसिया रौब दिखाया। आरोप यह भी है कि एक मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। यद्यपि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच और पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी शेष है, फिर भी यह घटनाक्रम लोकतंत्र, पत्रकारिता और पुलिस जवाबदेही पर व्यापक चर्चा की माँग करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पत्रकार भीड़ का हिस्सा है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वह न सत्ता का प्रतिनिधि होता है और न ही विपक्ष का। उसका दायित्व जनता और शासन के बीच सूचना का सेतु बनना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, पत्रकार उसी अधिकार का सामाजिक विस्तार है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण से जुड़े पत्रकार पिछले लगभग तीन दशकों से देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। वे अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस एसोसिएशनों तथा पत्रकार मंचों से जुड़े रहे हैं और जनसरोकार, प्रशासनिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ग्रामीण भारत से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं। ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ और मान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार या धमकी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की गरिमा का नहीं रह जाता, बल्कि पत्रकारों की कार्य-स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। यदि पत्रकार भयमुक्त नहीं रहेगा, तो जनता तक सत्य और सूचना का प्रवाह भी बाधित होगा। इसलिए किसी पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक




मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन जाता है। दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। झारखंड जैसे राज्य में पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण है। राज्य लंबे समय तक नक्सलवाद, संगठित अपराध, अवैध खनन, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनावों जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। हाल के वर्षों में झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण और उग्रवाद विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी और साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं। गोड्डा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले में समय-समय पर अवैध हथियारों, आपराधिक गिरोहों, भूमि विवादों तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे हैं। ऐसे में पुलिस को कई बार त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी कार्रवाई की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया से भी तय होती है। यही वह बिंदु है जहाँ नागरिक अधिकारों और पुलिस शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस पूछताछ करती है तो नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उससे पूछताछ करने वाला व्यक्ति कौन है और किस अधिकार के तहत कार्रवाई कर रहा है। सवाल यह भी है कि यदि पुलिस सादे वेश में कार्रवाई कर रही हो तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज के दौर में जब अपराधी भी स्वयं को पुलिस बताकर लोगों को ठगने लगे हैं, तब आम नागरिक के मन में संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए पारदर्शिता केवल नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड के सामने अपराध नियंत्रण की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और आर्थिक अपराध जैसी समस्याएँ राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को अधिक अधिकार और संसाधन मिलना चाहिए, लेकिन उतनी ही मजबूती से जवाबदेही की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत नागरिक पर भी लागू होता है और वर्दी पर भी। पुलिस की शक्ति संविधान से आती है, भय से नहीं। यदि किसी नागरिक या पत्रकार को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे शिकायत करने, जाँच की माँग करने और न्याय पाने का अधिकार है। आज आवश्यकता पुलिस बनाम पत्रकार की बहस की नहीं है। आवश्यकता पुलिस और पत्रकार के बीच विश्वास बहाली की है। दोनों ही लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है और पत्रकार उस कार्रवाई को जनता तक पहुँचाता है। दोनों का लक्ष्य अंततः जनहित ही है। यदि लालपुर की घटना में लगाए गए आरोप गलत सिद्ध होते हैं, तो इससे पुलिस की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। यदि कहीं किसी स्तर पर चूक या दुर्व्यवहार पाया जाता है, तो निष्पक्ष कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में सत्य, पारदर्शिता और विधि का शासन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। झारखंड पुलिस के हजारों अधिकारी और जवान कठिन परिस्थितियों में दिन-रात सेवा दे रहे हैं। उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि आम नागरिक, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्ग स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। लोकतंत्र में वर्दी का सम्मान और नागरिक की गरिमा—दोनों साथ-साथ चलते हैं। कानून का राज केवल अपराधियों को पकड़ने से स्थापित नहीं होता। कानून का राज तब स्थापित होता है जब आम आदमी बिना भय के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, पत्रकार बिना दबाव के प्रश्न पूछ सके और पुलिस बिना पक्षपात के कानून लागू कर सके। गोड्डा की यह कथित घटना चाहे जिस निष्कर्ष तक पहुँचे, उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा किया है—क्या हम भय आधारित व्यवस्था चाहते हैं या विश्वास आधारित शासन? लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संविधान उससे भी ऊपर है। पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह जनता की आवाज़ है। और सबसे बढ़कर, आम नागरिक का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी है। जब वर्दी में संवेदनशीलता होगी, कलम में निर्भीकता होगी और नागरिक के मन में विश्वास होगा, तभी झारखंड की कानून-व्यवस्था वास्तव में मजबूत मानी जाएगी। यही लोकतंत्र की आत्मा है, यही संविधान की भावना है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी।

# मादक पदार्थों का बढ़ता साम्राज्य और सिमटते सपने



लेखक- योगेश कुमार गोयल

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के सपनों, ऊर्जा और सृजनशीलता पर निर्भर करता है लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने लगे तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लेती है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के सामने यही चुनौती खड़ी है। युवाओं की प्रतिभा, उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता और उनके भविष्य पर नशे का ऐसा ग्रहण लग रहा है, जो न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहा है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी मानवता को चेताने का अवसर है कि यदि नशे के बढ़ते दुष्चक्र को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। भारत में नशे की समस्या अब महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और यहां तक कि स्कूलों तथा कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। कभी माना जाता था कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल संपन्न वर्ग या शहरी संस्कृति की समस्या है लेकिन आज वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि नशे का नेटवर्क अब समाज की हर परत तक पहुंच चुका है। आज का युवा अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद, अकेलापन और त्वरित सफलता की चाह उसे भीतर से कमजोर बना रही है। ऐसे में नशे के सौदागर युवाओं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मित्रों का दबाव, आधुनिक दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या क्षणिक सुख का आकर्षण युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है लेकिन धीरे-धीरे यही जिज्ञासा लत और फिर विनाश का कारण बन जाती है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने जहां ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, वहीं नशे के कारोबार को भी नए साधन उपलब्ध कराए हैं। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब नशे का सौदा किसी सुनसान गली तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की पहुंच चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जिन परिसरों में देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए, वहां कुछ युवा अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करने की राह पर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। कई युवाओं को यह भ्रम होता है कि नशा उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आधुनिक बनाता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरणशक्ति प्रभावित होती है, एकाग्रता घटती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जो युवा अपने जीवन में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है, वही नशे की गिरफ्त में आकर अपनी प्रतिभा और संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। यही कारण है कि नशे को केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के विनाश की समस्या माना जाता है। नशीले पदार्थों का सबसे घातक प्रभाव यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से गुलाम बना देते हैं। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक मात्रा में नशा लेने लगता है। परिणामस्वरूप उसका शरीर कमजोर होने लगता है, भूख कम हो जाती है, वजन घटता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मामलों में व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों के सामने खतरा और भी गंभीर होता है। एक ही सुई के बार-बार उपयोग से एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

## ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से रौंदा, नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

**मियामी ।** ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने दो गोल दागे, जबकि मैथियस कुन्हा ने एक गोल किया। इस मुकाबले में नेमार की लंबे समय बाद ब्राजील की टीम में वापसी हुई। ब्राजील ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और स्कॉटलैंड पर लगातार दबाव बनाए रखा। मैच के छठे मिनट में ही ब्राजील ने 1-0 की बढ़त हासिल की। स्कॉटलैंड के डिफेंस

से हुई गलती का फायदा उठाते हुए विनीसियस जूनियर ने शानदार गोल दागा। विनीसियस ने यह टूर्नामेंट का अपना चौथा गोल दागा और वह इस गोल के साथ ही गोल्डन बूट की रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने किलियन एम्बाप्पे और एरलिंग हालैंड की बराबरी कर ली है। पहले गोल के बाद भी ब्राजील का दबदबा जारी रहा। विनीसियस ने एक और गोल किया था, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वीएआर) की जांच के बाद उसे फाउल करार देते हुए रद्द कर दिया गया। हालांकि, पहले हाफ के अतिरिक्त समय में विनीसियस ने हाथ आए मौके को भुनाया और ब्राजील को मैच में 2-0 से आगे कर दिया। ब्रूनो गिमाराइश के बेहतरीन क्रॉस पर विनीसियस ने शानदार हेडर मारते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया।

# मैक्सिको ने रचा इतिहास

● पहली बार वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में किया क्लीन स्वीप ● 22 साल के चावेज से 40 वर्षीय ओचोआ तक

**नई दिल्ली।** फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियम में चेक गणराज्य के लुकास सर्वे से गेंद छीनने की कोशिश में मैक्सिको के गुइलेर्मो मार्टिनेज और सीजर मोंटेस। चेक रिपब्लिक के रॉबिन हरनाक के साथ गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए संघर्ष करते हुए मेक्सिको के सैंटियागो जिमेनेज (दाएं)। (फोटो सोर्स- रायटर्स)

22 साल के माटेओ शावेज के पहले वर्ल्ड कप गोल से लेकर 40 वर्षीय गुइलेर्मो ओचोआ के ऐतिहासिक छठे वर्ल्ड कप तक, मैक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हरा पहली बार टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया।

मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुका था। अब उसने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए शान से अगले दौर में कदम रखा। चेक गणराज्य केवल एक अंक ही हासिल कर पाया और वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया।

### पहले 2 जीत और एक ड्रॉ था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

ग्रुप स्टेज में मैक्सिको का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1986 और 2002 में रहा था, जब टीम ने 2 जीत और एक ड्रॉ हासिल किया था। दोनों विश्व कप में जैवियर एगुइरे शामिल थे।

पहली बार खिलाड़ी के तौर पर और दूसरी बार मैक्सिको के कोच के रूप में। एगुइरे इस साल फिर टीम के कोच हैं और यह उनका राष्ट्रीय टीम के साथ तीसरा कार्यकाल है।

मैक्सिको ने 6 मिनट के भीतर दागे 2 गोल

माटेओ शावेज और जूलियन क्विनोनेस ने दूसरे हाफ की शुरुआत में 6 मिनट के अंतराल में गोल किये। अपना पहला विश्व कप खेल रहे शावेज ने 55वें मिनट में गोल किया। क्विनोनेस ने 61वें मिनट में गोल दागा।

### 11 मैच से अपराजित है मैक्सिको

भारतीय समयानुसार गुरुवार यानी 25 जून 2026 की सुबह यह स्टेडियम 80824 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। एल ट्राइ (मैक्सिको की टीम का उपनाम) को एज्टेका स्टेडियम में केवल दो बार हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें से उसे आखिरी हार छह सितंबर 2013 को होंडुरास के खिलाफ विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में मिली थी। पिछले नवंबर में पनामा के खिलाफ मैत्री मैच में मिली हार के बाद से मैक्सिको 11 मैचों में अपराजित रहा है।

**समलैंगिक विरोधी नारों ने लगाया जीत पर दाग-** मैक्सिको की जीत पर हालांकि प्रशंसकों द्वारा समलैंगिक विरोधी नारे लगाने से दाग लग गया। इस कारण पहले भी उसके फुटबॉल महासंघ पर जुर्माना और अन्य प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।

### अतीत और भविष्य दोनों की झलक

इस मैच में मैक्सिको के अतीत और भविष्य दोनों की झलक देखने को मिली। गिलबर्टो मोरा 17 साल की उम्र में विश्व कप में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले मैक्सिको के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। दूसरी तरफ 40 वर्षीय गोलकीपर गुइलेर्मो 'मेमो' ओचोआ 77वें मिनट में मैदान पर उतरे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ छह विश्व कप में खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। ग्रुप ए का विजेता बन चुका मैक्सिको मंगलवार 30 जून को एज्टेका स्टेडियम में राउंड ऑफ-32 के मैच में एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलेगा जिसका अब तक निर्धारण नहीं हुआ है। मैक्सिको ने इस विशाल स्टेडियम में खेले गए नौ विश्व कप मुकाबलों में से एक भी मैच नहीं हारा है।

### चीन को उसके घर में मात देने वाली भारतीय बेटियों को आनंद महिंद्रा का सलाम

# 'हमें ऐसी उपलब्धियां और चाहिए'

नई दिल्ली। भारत की बेटियों ने रविवार 21 जून को हॉकी की फील्ड पर इतिहास रचा था और एफआईएच नेशंस कप जीता था। उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड 4×100 मीटर रिले में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचा। श्रावणी नंदा, एसएस स्नेहा, सुदेष्णा शिवंकर और तमन्ना की चौकड़ी ने भारत को एशियन रिले चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया। भारतीय महिला रिले टीम की इस जीत के बाद विख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी टीम की जमकर तारीफ की।

आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल पर महिला रिले टीम की जीत का वीडियो शेयर किया। उन्होंने टीम की सराहना करते हुए खास मैसेज लिखा और यह भी बताया कि वह बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक चीन को चीन में हराकर गोल्ड जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में इस चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 3 मेडल अपने नाम किए।

### क्या बोले आनंद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा ने भारतीय महिला रिले टीम की जीत का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा,'एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के खिलाफ जीतन में जीत दर्ज करना बेहतरीन उपलब्धि।

4म100 मीटर रिले में श्रावणी, सुदेष्णा, स्नेहा और तमन्ना ने अपने टीम वर्क से पॉवर, स्पीड, ग्रेस और कमिटमेंट को दिखाया। मैं इस क्लिप (टीम की जीत के वीडियो) को बार-बार लूप में देख रहा हूं। हमें ऐसी और उपलब्धियां चाहिए हैं।'

**भारतीय रिले टीम का सीजन बेस्ट प्रदर्शन-** भारतीय रिले टीम ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में 43.85 सेकंड का सीजन-बेस्ट टाइम निकाला। भारतीय टीम इस प्रदर्शन के साथ टॉप पर रही और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही चीन की टीम जिसने 44.09 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता।

### भारत के नाम एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज

मिक्स्ड 4म100 मीटर रिले में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तमन्ना और स्नेहा ने अनिमेष कुजूर और प्रणव गुरव के साथ इस इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद मिक्स्ड 4म400 मीटर रिले में थीर्थेश पी शेट्टी, एमआर पूवम्मा, भारत श्रीधर और नीरू पाठक ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस चौकड़ी ने 3 :17.06 सेकंड के समय के साथ देश के नाम रजत पदक किया।

## व्यापार

# ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो मिलेगा 25000 तक का मुआवजा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के शिकार होने वाले लोगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसे उसके नुकसान का 85% या 25000 रुपये (जो भी कम हो) मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

आरबीआई का यह नया सुरक्षा कवच उन मामलों में भी काम करेगा जहां ग्राहक ने गलती से अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी जालसाज के साथ साझा कर दिया हो। यह संशोधित नियम जनवरी 2027 से लागू होने जा रहे हैं। पहले इसे जल्द लागू किया जाना था, लेकिन बैंकों की तकनीकी और प्रणालीगत तैयारियों को देखते हुए आरबीआई ने इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीआई ने धोखे

से किए गए लेनदेन की परिभाषा को और कड़ा किया है। इससे पहले के ड्राफ्ट में जिन मामलों में ग्राहकों को डरा-धमकाकर या चालाकी से उनकी क्रेडेंशियल्स (पासवर्ड/ओटीपी) ली जाती थी, उन्हें अधिकृत लेनदेन मान लिया जाता था। लेकिन अब आरबीआई ने इस परिभाषा को सुधारकर ग्राहकों के पक्ष में कर दिया है। अगर आपने कोई सामान खरीदा जो खराब निकला या सेवा समय पर नहीं मिली, तो ऐसे विवाद इस मुआवजे के दायरे में नहीं आएंगे। बैंकों के पास अब घरेलू धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच और समाधान के लिए 45 दिन का समय होगा। पहले ड्राफ्ट में यह सीमा 30 दिन थी। विदेशी लेनदेन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बैंकों को 60 दिन का समय मिलेगा।

# एयरलाइन को किराया कम करने को कह सकती है सरकार, लेकिन यह होना जरूरी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें नरम होने लगी हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से एयर फेयर में कटौती के हालात बनने लगे हैं। सरकार का कहना है कि एक बार क्रूड की कीमतें स्टेबल हो जाए तो फिर वह एयरलाइनों से सर्ज चार्ज और अतिरिक्त किराए की समीक्षा करने के लिए कह सकती है। यह जानकारी केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने दी है। नायडू ने बताया कि इस समय केंद्र सरकार हर पखवाड़े एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों की समीक्षा करता है। यह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की गति पर आधारित होती है। इसके अलावा, इसने एयरलाइनों को संकट के समय समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष भी बनाया है। नायडू ने बताया कि केंद्र एटीएफ की कीमतों पर करीबी नजर रख रहा है और हाल की कीमतों में गिरावट स्थायी है या नहीं, यह आंकने के लिए एयरलाइनों से चर्चा कर रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा 'दूसरे, अब जब हम कीमतें कम होते देख रहे हैं, हमें अभी यह देखना होगा कि यह दीर्घकालिक कमी है या अचानक हुई गिरावट, और हम इस पर एयरलाइनों से बात कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने सिविल एविएशन सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। किराए से संबंधित किसी भी फैसले की निर्भरता ईंधन की कीमतों की स्थिरता पर होगी। उन्होंने कहा, 'पिछले 4 महीने एयरलाइंस के लिए काफी अहम रहे हैं। एक बार जब हम स्पष्ट हो जाते हैं कि कीमतों में स्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी, तो हम उनसे बात करेंगे और सर्ज चार्ज या अतिरिक्त कीमतों को कम करने की दिशा में काम करेंगे, जो हम अभी देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से उपजे भू-राजनीतिक संकट के बीच, सरकार ने घरेलू शिड्यूल्ड ऑपरेटरों के लिए एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की कैपिंग कर दी गई है।

# जुलाई में आने वाली है 45000 करोड़ के आईपीओ की बाढ़, एसबीआई और जेपीटो समेत समेत ये बड़ी कंपनियां मचाएंगी धमाल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत का प्राइमरी मार्केट जुलाई में फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। पिछले कुछ महीनों की सुस्ती के बाद अब कई कंपनियां अपने लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। अगले महीने एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां बाजार से करीब 45,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही हैं।

इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कहना है कि अलग-अलग सेक्टर की कंपनियां अपनी लिस्टिंग की तैयारी तेज कर रही हैं, क्योंकि बाजार के हालात अब उनके पक्ष में हैं। सेंसेक्स निफ्टी में उतार-चढ़ाव के बाद अब मजबूती दिख रही है।

### किसका होगा सबसे बड़ा आईपीओ

सबसे बड़ा आईपीओ फंड्स मैनेजमेंट का हो सकता है, जो 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये के बीच होगा। इसके बाद मनिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का करीब 11,000 करोड़ रुपये और 8,000 करोड़ रुपये का आने की उम्मीद है। इन तीनों को मिलाकर ही करीब 32,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। जुलाई के पाइपलाइन में गजा कैपिटल, नैक पैकेजिंग, इनोवेटिव व्यू जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।

### निवेशकों का बढ़ रहा भरोसा

फाइनेंशियल की एमडी और सीईओ (इन्वेस्टमेंट बैंकिंग) सोनिया दासगुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में बाजार में लिस्टिंग की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। इसका कारण दुनिया भर में जारी अनिश्चितताओं का धीरे-धीरे कम होना और भारतीय निवेशकों का बाजार पर भरोसा बने रहना है।

### 173 कंपनियों को मिली मंजूरी

19 जून तक करीब 173 कंपनियों को सेबी से 2.7 लाख करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, 64 और कंपनियां सेबी की हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं।

### इस साल क्यों रही सुस्ती

साल 2025 की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) में जबरदस्त तेजी देखी गई थी, लेकिन इस साल की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। इसकी मुख्य वजह खाड़ी युद्ध जैसे वैश्विक तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कम निवेश रही। इस साल अप्रैल तक 18 आए थे, लेकिन मई में एक भी कंपनी बाजार में नहीं उतरी। जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक अनिश्चितता घटेगी। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

### निवेशकों को क्या पसंद

सोनिया दासगुप्ता का कहना है कि निवेशक उन्हीं कंपनियों को पसंद कर रहे हैं जिनकी बुनियाद मजबूत है। जहां ग्रोथ की उम्मीद है। जिनका बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिकने वाला है। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बाजार में काफी बढ़ रही है। इनमें हस्श्व का 30,000 करोड़ रुपये और जियो प्लेटफॉर्म्स का बड़ा भी शामिल है।

# हम भारत के लिए पूरी तरह तैयार हैं... दिल्ली आते ही ईरानी तेल मंत्री ने जता दिए इरादे, बड़ी ट्रेड डील के संकेत

**नई दिल्ली, एजेंसी।** ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सहयोग से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेने ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद नई दिल्ली पहुंचे हैं। बुधवार को भारत आगमन पर पाकनेजाद ने स्पष्ट किया कि ईरान भारत के साथ आर्थिक क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ईरानी तेल मंत्री ने कहा, 'ईरान और भारत के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इस समय मैं यहां ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आया हूं। इस सम्मेलन के दौरान और द्विपक्षीय वार्ताओं में जो भी चर्चा होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। हम भारत के साथ आर्थिक क्षेत्रों, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में हर संभव सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं।'

**60 दिनों की छूट पर बड़ा बयान:** अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के सवाल पर मोहसिन पाकनेजाद ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रतिबंधों का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, हमें फिलहाल 60 दिनों की छूट मिली हुई है। हम इस संबंध में अमेरिकियों के साथ हुए समझौते के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों के समापन के बाद ही वह इस विषय पर आगे कोई विस्तृत टिप्पणी कर पाएंगे।

**द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य एजेंडे:** अपनी इस यात्रा के दौरान ईरानी पेट्रोलियम मंत्री भारतीय अधिकारियों और देश के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इस रणनीतिक दौरे के मुख्य एजेंडे में ये मुद्दे शामिल हैं: तेल और गैस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना। दोनों देशों के बीच नए निवेश के अवसरों की तलाश। वैश्विक ऊर्जा बाजार के मौजूदा हालातों और भविष्य के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान।

होर्मुज खुलने से वहां से तेल के टैंकर आसानी से निकलने लगे हैं। ऐसे में कच्चे तेल के दाम में गुरुवार को भी गिरावट आई। गुरुवार सुबह 9 बजे स्टेंडर्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.79 फीसदी या 1.32 डॉलर प्रति बैरल घट कर 72.42 डॉलर पर ट्रेड हो रहा था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)